राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 6

नवम्बर–दिसम्बर 2007

सामाजिक समता दिवस

6 दिसम्बर

संगठन गढ़े चलो
सुपंथ पर बढ़े चलो

अभाविप के शिल्पकार
यशवंतराव केलकर

Shri Sunil Ambekar (National Org. Secretary) addressing Swatanthrya Samara Sandesh Yatra conducted by ABVP Kerala to celebrate the 150 years of the first freedom struggle and the birth centenary of Bhagat Singh.

Shri Murali Manohar (National Vice President) inaugurating the 27th State Conference of Kerala at Palakkad on 2nd November.

दिल्ली प्रांत का 43वां अधिवेशन का उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार,जितेन्दर बजाज और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 30 अंक : 6 ● नवम्बर–दिसम्बर 2007

संरक्षक
अतुल कोठारी
संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल
प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhatrashakti@yahoo.co.in
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

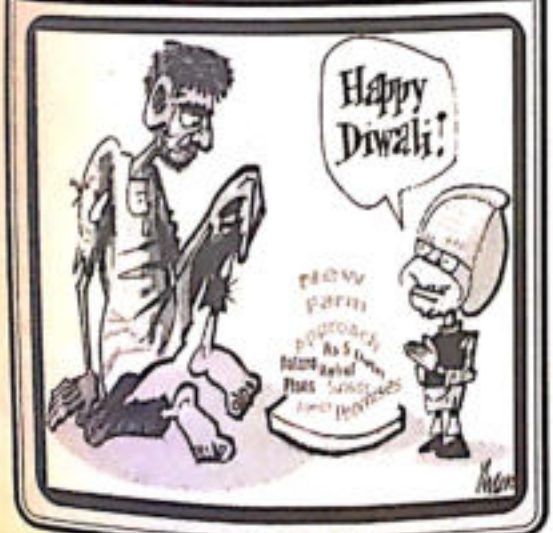

विषय सूची

प्रमुख लेख

पश्चिम में घुलती हिंदी भाषा.....6
अभाविप के शिल्पकार – यशवंतराव केलकर.....7
भारत की पहचान का आंदोलन था 1857 का महासमर.....9
लाल झंडे के नीचे दमन की दास्तान.....13
महंगाई और मुद्रास्फीति का सच.....15
आजादी के 60 वर्ष, उपलब्धियां एवं चुनौतिया.....17
विरासत की वापसी की व्यथा.....19
कहीं देर न हो जाए.....23

मुलाकात

अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री बी. सुरेन्द्रन.....25

परिचर्चा

भारत में अल्पसंख्यक कौन?.....21
परिषद् गतिविधियां.....28

आह्वान

* क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
* क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम हैं?

यदि हां

* तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए, आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।
* अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 136, नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली–110001 को प्रेषित करें।

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

डॉ. रामनरेश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा श्री सुरेश भट्ट राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पुनर्निवाचित

डॉ.रामनरेश सिंह

सुरेश भट्ट

डॉ. रामनरेश सिंह (सहरसा, बिहार) और श्री सुरेश भट्ट (वाराणसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश) देश के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री के पद के लिये पुनर्निर्वाचित हुए है। यह घोषणा अभाविप केन्द्र कार्यालय (मुंबई) से की गई।

अभाविप केन्द्र कार्यालय से चुनाव अधिकारी डॉ. कैलाश शर्मा द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार दोनों पद का कार्यकाल एक वर्ष (2007–2008) रहेगा और दोनों पदाधिकारी कानपुर (उत्तर प्रदेश) में दि. 1 दिसम्बर 2007 से प्रारंभ होने वाले 53 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

डा. रामनरेश सिंह, भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय (सहरसा, बिहार) में मैथिली स्नातकोत्तर विभाग के उपचार्य है। तथा गत 18 वर्षो से अभाविप में सक्रिय है। डॉ. रामनरेश सिंह का राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर गहरा अध्ययन है। आपके आलेख आई.ए. तथा एम.ए. के पाठयपुस्तकों में संकलित होते रहे है। देश–विदेश के कई संस्थानों के द्वारा आपको हिन्दी साहित्य भाषा में सेवा एवं सहयोग हेतु पुरस्कृत किया गया है। बिहार में विद्यार्थी परिषद कार्य मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. रामनरेश सिंह ने नगर अध्यक्ष, बिहार प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसे विभिन्न जिम्मेदारी का निर्वाह विद्यार्थी परिषद में किया है। वे 2006 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिये चुने गए एवं दुसरी बार पुनः नये सत्र के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए है।

श्री सुरेश भट्ट मूलतः उत्तरांचल के नैनीताल जिले के है। 1988 से अभाविप के सम्पर्क में है। उन्होंने एम.ए. भूगोल, एल.एल.बी. तक की शिक्षा पूरी की है। वे महाविद्यालय के दिनों से अभाविप के सक्रिय कार्यकर्ता रहे है। आप 1992 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय अल्मोडा के छात्रसंघ अध्यक्ष भी रहे है। श्री सुरेश भट्ट शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् 1994 से अभाविप के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहे है। जिला प्रमुख, विभाग संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री, प्रान्त मंत्री, प्रान्त सह संगठन मंत्री, प्रान्त संगठन मंत्री आदि दायित्वों का निर्वाह किया है। 1999 से 2003 तक आप अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री रहे है। आपका केन्द्र वाराणसी है। वे 2006 में राष्ट्रीय महामंत्री के लिये चुने गये। तथा दूसरी बार पुनः नये सत्र के लिये राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए है। श्री सुरेश भट्ट श्रीराम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान गिरफतारी में तिहाड़ जेल गये तथा पृथक उत्तरांचल राज्य निर्माण आन्दोलन में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही।

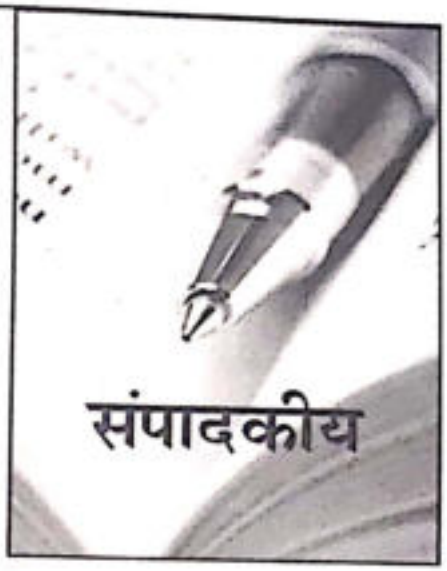

नंदीग्राम नरसंहार माकपा को ले डूबेगा

बंगाल के डायर बने बुद्धदेव

पश्चिम बंगाल में पिछले 30 सालों से माकपा सत्तासीन है। माकपा का इतना लंबा राज्य आतंक के दम पर ही रहा है। नंदीग्राम में कानून और संविधान का नहीं, बल्कि आतंक का शासन चलता है। वामपंथियों का कभी भी लोकतन्त्र पर विश्वास नहीं रहा है। वे तानाशाही विचारधारा में विश्वास करते हैं। गौरतलब है कि नंदीग्राम में इंडोनेशियाई औद्योगिक घराने सलीम समूह के प्रस्तावित रासायनिक कारखानों के लिए वामपंथी सरकार किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है। यह भूमि बेहद उपजाऊ है और उस पर साल में चार फसलें पैदा होती है। इस भूमि के अधिग्रहण से एक लाख किसान बेदखल होंगे। इसके विरोध में वहां के लोगों का संघर्ष लगातार जारी है।

गत 14 मार्च, 2007 को नंदीग्राम में अपना हक मांग रहे किसानों पर वाम मोर्चा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जमकर गोलियां बरसाईं, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तब से लेकर वहां निरंतर गोलीबारी–बमबाजी जारी है। गांव और खेत से किसान खदेड़े जा रहे हैं। अब तक दो सौ से ज्यादा लोग मारे गये। दो सौ लोग अब भी लापता हैं।

नंदीग्राम नरसंहार भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 1919 के जलियांवाला बाग के डायर साहब को भी लज्जित कर दिया। अपना हक मांग रहे किसान, मजदूर और महिलाओं पर माकपाई कैडर जुल्म ढा रहे हैं। जुल्म ऐसे कि दिल दहल जाता है। रोंआ–रोंआ कांप उठता है। पुलिस देखती रही और माकपा के लोग नंदीग्राम में खून बहाते रहे। नरसंहार के बाद कई दर्जन महिलाओं को बलात्कार का शिकार भी बनाया गया। सैकड़ों घरों को लूट लिया गया। आग के हवाले कर दिया गया। लाशों के ढेर लगा दिए गए। सिंगूर में भी सरकार ने किसानों की उपजाऊ जमीन छीनने का प्रयास किया। वहां भी माकपा ने मानवता को शर्मशार कर दिया। सरकारी दमन का विरोध कर रही तापसी मलिक का वामपंथी गुंडों ने हाथ–पैर–मुंह बांध दिया और बारी–बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसे एक जलती भट्टी में डाल दिया गया। वामपंथी बुद्धिजीवी महाश्वेता देवी ने कहा है कि माकपा काडर ने हिंसा के दौरान औरतों के गुप्तांगों में गोली मारी और लोहे की छड़ घुसाकर चीर दिया। पिछले दिनो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर जब नंदीग्राम की तरफ जा रही थीं तो उनके वाहन को रोका गया और उनके एक सहयोगी को पीटा गया। उन्होंने कहा कि माकपा के गुंडों ने उन्हें भी बाल पकड़कर खींचा।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने साहस का परिचय देते हुए कहा कि नंदीग्राम युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया है। कोई भी सरकार या समाज ऐसे किसी युद्धक्षेत्र को बने रहने की अनुमति नहीं दे सकती है, वो भी बिना किसी तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के। इसके जवाब में वाम गठबंधन के प्रमुख बिमान बोस ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया है।

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी वाम गठबंधन के घटक दलों में मतभेद उभर आए हैं। आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और भाकपा ने नंदीग्राम की हिंसा के लिए सीधे–सीधे माकपा को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र की सरकार 64 वामपंथी सांसदों के समर्थन पर टिकी है इसलिए कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। यूपीए सरकार की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नंदीग्राम जाने का साहस नहीं जुटा पाए। कारण साफ है केन्द्र सरकार वामपंथियों के वैशाखी तले टिकी है। नंदीग्राम नरसंहार ने माकपा के किसान, मजदूर और महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया हैं। गत 85 वर्षों से भारत में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी महज तीन राज्यों में ही सिमटे हुए है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नंदीग्राम नरसंहार के बाद वे और सिकुड़ जाएंगे।

पश्चिम में धुलती हिंदी भाषा

- प्रीया डबास -

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में पाश्चात्य सभ्यता अपनी छवि इस तरह से छोड़ती जा रही है, की हिन्द देश में रहकर हम अपनी हिन्दी भाषा की अवहेलना कर रहे है। और यह अवहेलना भी हमें गर्व का अनुभव कराती है। ऐसा गर्व जो हमें आधुनिक होने का एहसास दिलाता है।

भाषा ही सर्वप्रथम हमें किसी व्यक्ति विशेष की ओर आकृषित करती है। उसकी सरल, सुग्म और प्रभावी भाषा हमें उस व्यक्ति के गुणों व व्यक्तित्व से परिचित कराती है। परन्तु आधुनिकता की इस दौड़ में शामिल होने के लिए हम अपनी धरोहर, अपनी भाषा को छोड़कर, अन्य किसी भाषा पर ध्यान केन्द्रित कर रहे है। ताकि अपने आधुनिक होने का प्रमाण दे सके। लेकिन ऐसे प्रमाणों का कोई औचित्य नही रह जाता जो आपको स्वयंकी भाषा से दूर करे।

इसमे कोई सशय नहीं है कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है, परन्तु इसका अर्थ ये कतई नहीं लगाना चाहिए की हम अपनी स्वयं की भाषा को पीछे छोड़कर पश्चिमी भाषा को अपनाने में इतने आगे निकल जाए की ना इसे ही अपनी कह पाए और जो अपनी है उसे भी खो बैठे। हम क्यों पराई भाषा के पीछे दौड़ रहे है। क्यों हमें हिन्दी पसंद नहीं आ रही है। क्या बच्चे के मुख से पहली बार निकला शब्द मदर होता है। शायद नही। चाहे किसी भी तरह कोशिश की जाए पहली धुन तो माँ शब्द की ही होती है। हम पश्चमी भाषा अपनाकर ये सिद्ध करने की कोशिश करते है कि हम आपके साथ–साथ चल रहे है। अपकी बराबरी में उन्नति कर रहे है।

हमें हिन्दी भाषा निम्न स्तर की दिखाई देती है। जबकि आज UNO में हिन्दी भाषा के विस्तार की बात चल रही है।

देश का एक महान नेता श्री अटल बिहारी जी, भारत का नेतृत्व करते हुए UNO की सभा में हिंदी में भाषण देकर अपने को गौरवपूर्ण महसूस करता है। तो हमें देश मेंही अपनी भाषा पर कैसी शर्म?

वैश्वीकरण की दौड़ में हमसे पहले चीन का नाम आता है लेकिन उनकी एक खासीयत रही है, की किसी भी सूरत में उन्होनें अपनी भाषा से नाता नही तोड़ा है। आज स्थिति ऐसी बन आई है कि हमें हिंदी को बचाने के लिए आन्दोलन समारोह आदि करने पड़ रहे है।

अंग्रेजी का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि हम अपनी मातृभाषा को पहचान दने से इन्कार कर रहे है। आवश्यक है की हम एक वैश्वीक भाषा आनी चाहिए। परन्तु इसका ये अर्थ नहीं की हिन्दी के ही अस्तित्व को खतरे में डालकर चले। अपनाने के लिए तकनीक हो सकती है संस्कृति नहीं। छोडने के लिए पहचान हो सकती है भाषा नहीं। ■

UPSC Chairman summoned for allegedly using the word 'terrorist' to describe Sardar Bhagat Singh.

The Union Public Service Commission (UPSC) Chairman has been summoned by a local court of Kanpur in connection with a question paper prepared by the Commission which allegedly used the word 'terrorist' to describe Sardar Bhagat Singh.

The General Studies paper of Civil Services Examination (mains) had allegedly used the word 'terrorist' for the famous freedom fighter. The summon issued by the court of Chief Metropolitan Magistrate R K Bansal has asked the UPSC Chairman to appear before it on November one.

The summon follows a petition filed in the Chief Metropolitan Magistrate's court demanding action against the UPSC Chairman under sections 500, 501 and 502 of the IPC for using the word 'terrorist' for the great freedom fighter and hurting the sentiments of the people of the country. A report from Varanasi said Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) activists took out a procession there in protest against the 'blunder' and burnt the effigy of the UPSC Chairman.

अभाविप के शिल्पकार - यशवंतराव केलकर

राजकुमार भाटिया
[अभाविप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष]

भारत के सार्वजनिक जीवन में एक अनुभव बहुत आता है और वह है राष्ट्रीय–सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाने वाले महान व्यक्तियों में से कुछ का अतिवादी उल्लेख एवं कुछ का अतिअल्प उल्लेख। हो सकता है सार्वजनिक जीवन के इतिहास की यह विडंबना संपूर्ण विश्व में लागू होती हो या फिर भारत में इसकी मात्रा अधिक हो।

जो भी हो अनुभव में यह आ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय समाजिक जीवन में अद्वितीय योगदान करने वाला एवं 1925 में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय संगठन–राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ–संगठन के नाते एवं उसमें विशेष भूमिका निभाने वाले अनेकों स्वयं सेवक व्यक्ति के नाते अतिअल्प उल्लेख के शिकार हो रहे है।

ऐसा क्यों हो रहा है इसकी कारण मीमांसा इस छोटे लेख की विषय वस्तु नहीं है। अभी कहने का हेतु यह है कि प्रा. यशवंत राव केलकर भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे जिनका उल्लेख अतिअल्प हुआ है।

यशवंतराव मूलतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक व कार्यकर्ता थे परंतु उनके जीवन का अधिकांश समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य में बीता था। संघ उनकी प्रेरणा था और अभाविप उनकी कर्मभूमि।

यूं तो अभाविप 1948 में प्रारंभ हुई और 1949 में उसका पंजीकरण हुआ परंतु व्यवस्थित, नियोजित और नियमित रूप से उसका कार्य 1958 से प्रा. यशवंत राव के संयोजकता में प्रारंभ हुआ । इसी कारण प्रा. केलकर को अभाविप शिल्पी कहा जाता है। परिषद की स्थापना के समय से ही उसकी एक विशेषता रही कि उसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक भी कार्यरत रहे। अभाविप देशका एकमात्र छात्र संगठन है जिसमें अध्यापक कार्यकर्ता भी होते है और पदाधिकारी भी। यशवंतराव एक प्राध्यापक के रूप में अभाविप से जुड़े। वे जब परिषद में सक्रिय हुए तब उनकी आयु 33 वर्ष थी। वे एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परिषद में प्रविष्ट हुए। 17 वर्ष से संघ स्वयं सेवक व कार्यकर्ता और उसी नाते 7 वर्ष संघ प्रचारक व 3 वर्ष जनसंघ के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय मंत्री का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया हुआ था। उनके रूप में अभाविप को एक दृष्टि संपन्न संगठक प्राप्त हुआ जिसने क्रमशः मुंबई, महाराष्ट्र एवं संपूर्ण देश की अभाविप का विकास किया। राष्ट्र निर्माण के कार्य में विद्यार्थियों के योगदान के अभाविप के उद्देश्य के अनुरूप संगठन का तंत्र व गतिविधियां खड़ी होती जायें इस स्पष्ट दृष्टि से वे एक एक कदम चलते गए और दस वर्षों में उन्होंने विद्यार्थी परिषद की वह नींव डाल दी जिस पर भारत का ही नहीं अपितु सभवतः पूरे विश्व का स्वतंत्र, संपूर्ण एवं स्थायी छात्र संगठन खड़ा हो सका। अभाविप का 1968 में मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग ही वह नींव थी जिससे अभाविप में कार्यकर्ता प्रशिक्षण व निर्माण, व्यक्ति नहीं संगठन आधारित सामाजिक सक्रियता एवं गंभीर चिंतन मनन एवं योजना निर्माण की परंपरा रूढ़ हुई।

व्यक्ति जीवन में यशंवत राव सामाजिक प्रतिबद्धता वाले आदर्श गृहस्थ नागरिक थे जिनकी मान्यता थी कि उपदेश से नहीं स्वयं के उदाहरण प्रस्तुति से व्यक्ति को राष्ट्रनिर्माण का कार्य करना चाहिए। इसको वे प्रथम पुरूषी विचार व व्यवहार कहते थे। उनकी मान्यता थी कि समाजिक कार्यकर्ता को यश, पद और प्रसिद्धि की आकांक्षा से दूर रहना चाहिए और कर्तव्यनिर्वहन को महत्व देना चाहिए। उन्होंने उसी के अनुरूप जीवन जिया। वे केवल एक वर्ष अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जबकि लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने बिना शीर्ष पद पर रहते हुए परिषद का नेतृत्व किया।

उनकी मान्यता थी कि सामाजिक कार्य संगठन के द्वारा अधिक प्रभावी रूप से सिद्ध होता है, संगठन व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति में गुण दोष दोनों होते हैं। इसलिए उनके लिए सामाजिक कार्य का अर्थ था संगठन निर्माण और सगठन के लिए आवश्यक था व्यक्तियों को गुण दोषों सहित जोड़ना। यशवंतराव ने जीवन भर इसी कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया।

यशवंतराव गृहस्थी भी थे और अध्यापन उनका व्यवसाय था। उनकी सोच थी कि सामाजिक कार्य करते हुए व्यक्ति को

वनवासियों ने बगावत की, जो धीरे–धीरे समूचे भारत में फैलती चली गयी।

रांची जिले के तमाड़ थाना में अंग्रेज अधिकारियों के विरूद्ध 1789 में विद्रोह हुआ। 1794–95 में यहां एक बार फिर विद्रोह हुआ। पुनः 1805 और 1820 में यहां जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातियों के इस विद्रोही तेवर ने धीरे–धीरे किसानों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट किसानों ने 1813–14 और 1831 के बीच देश भर में कई स्थानों पर विद्रोह किया। 1831 का किसान आंदोलन इतना तीव्र था कि इसे दबाने में अंग्रेजों को तीन वर्ष लग गए।देश का कोई भी कोना छिट–पुट होने वाले विद्रोहों से अछूता नहीं था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बिहार, हर स्थान पर कहीं किसानों ने तो कहीं स्थानीय कबीलाई समुदायों ने अंग्रेजों के विरूद्ध झंडा उठाया। बिहार के संथाल परगना में सिद्धू–कान्हू ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें दस हजार संथालों ने अपना बलिदान दिया। असम में खासी समुदाय के साथ अंग्रेजों के अमानुषिक व्यवहार, सार्वजनिक अवहेलना, उपेक्षा आदि के परिणामस्वरूप खासियों का जो विद्रोह फूटा उसे दबाने के लिए अंग्रेजों को चार साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।

अंग्रेजों के जुल्मों से परेशान भीलों ने भी अंततः 1818 में विद्रोह कर दिया, जो 1819 तक व्यापक स्तर पर फैल गया। भीलों के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने आठ हजार से अधिक भील विद्रोहियों को पकड़कर उनका अमानुषिक दमन किया। अंग्रेजों ने भीलों की रसद बंद कर दी, ताकि भूख से तंग आकर वे विद्रोह का रास्ता छोड़ दें। अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। अब तक जो छिट–पुट प्रतिक्रियाएं होती रही थी, उससे अलग 1857 में यह प्रतिकिया व्यापक रूप से सामने आई।

यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों को हमेशा इस बात का भय बना रहता था कि वनवासियों के इस विद्रोह का कहीं देशभर में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन से न रिश्ता जुड़ जाए। इसीलिए वनवासियों को समाज की मुख्यधारा से अलग रखने की अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश की। ब्रिटिश सरकार ने कई अधिनियम बनाकर गुर्जर, भील, दुसाध, मल्लाह आदि जो लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे, को अपराधी जाति घोषित कर दिया और उन्हें शिक्षा व नौकरी से पूरी तरह वंचित कर दिया। लेकिन विद्रोह की जो आग वनवासियों ने प्रज्जवलित की थी, उसकी तपिश से किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन भी अछूता नहीं रह सका।

अंततः 1857 में यह असंतोष महासमर के रूप में सामने आया और इस महासमर में सभी ने आपसी द्वेष को भुलाकर अंग्रेजों के विरूद्ध एक दूसरे का साथ दिया। 1857 के महासमर से पहले गांव–गांव में किसानों के बीच चपातियां बांटी गई। यह विद्रोह के लिए संगठित होने का संदेश था। हिन्दू–मुसलमानों ने अपने सारे विद्वेष भूलाकर इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ दिया था।

विद्रोह की पृष्ठभूमि उसी दिन बननी शुरू हो गई थी जब अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार का सिलसिला शुरू किया था। असंतोष को सुलगने और फिर ज्वाला बनने में एक सदी का समय अवश्य लगा। लेकिन यह कहना कि यह एक तात्कालिक घटना थी और इस विद्रोह में सिर्फ सैनिक शामिल थे, इतिहास का अधूरा सच होगा। यदि ऐसा होता तो किसान आंदोलन में शरीक नहीं होते। जगह–जगह जनजाति के लोग अंग्रेजों के विरोध में तीर कमान नहीं उठाते और धार्मिक अंतर्विरोधों को भुलाकर हिन्दू–मुस्लिम एक साथ इस महासमर में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़े होते।

स्पष्टतः 1857 का महासमर न केवल सिपाही विद्रोह था और न ही यह तात्कालिक असंतोष की उपज था। लगभग एक सदी का असंतोष ज्वाला बनकर राष्ट्रीय स्तर पर फूटा था, जिसमें सिपाहियों के साथ समाज के अन्य वर्गों और सभी समुदायों एवं धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया था। देश को आजाद कराने और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के साथ–साथ निरंकुशता का अंत करके शासन का पुनर्गठन और भारत की पहचान स्थापित करना विद्रोहियों का लक्ष्य था और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अंग्रेजों और उनके समर्थकों के विरूद्ध एकजुट होकर लड़े।

दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई सशस्त्र आन्दोलन नहीं हुआ जिसमें एक साथ करोड़ों लोगों ने भाग लिया हो। ऐसा भी कोई इतिहास नहीं मिलता जिसमें लाखों बलिदानों के बाद भी न आक्रमणकारियों के दमन रुके हों और न बलिदानियों का जोश ठंडा पड़ा हो। विश्व इतिहास की इस अनोखी मिसाल का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर, जिसने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंका और न केवल ब्रिटिश साम्राज्य आपितु भारत पर पिछले एक हजार साल से छाई गुलामी का मूलोच्छेद कर स्वतंत्र भारत के निर्माण की आधारशिला रखी।

दुनिया के तमाम देशों की संप्रभुता को निगल कर उन्हें अपना उपनिवेश बना चुके अंग्रेजों को 1857 के स्वातंत्र्य समर ने यह स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया कि वे इस देश को पाशविक शक्ति के प्रयोग अथवा धर्मान्तरण के द्वारा अपना स्थायी उपनिवेश नहीं बना सकेंगे। फूट डालो–राज

करो की जो नीति अंग्रेजों ने 1857 के बाद अपनायी वह इस स्वीकारोक्ति का ही प्रमाण है कि यदि भारत में जिस प्रकार की सामाजिक एकता स्वातंत्र्य समर के दौरान देखने को मिली, वह बनी रहती है तो कितने भी बलप्रयोग के बावजूद भारत को लम्बे समय तक अपने नियंत्रण में रख पाना संभव नहीं होगा।

जहां तक स्वराज्य प्राप्ति की बात है, देश के विभिन्न हिस्सों में हुए सैन्य संघर्षों में टुकड़ों–टुकड़ों में जीत हासिल की गयी किन्तु उसे स्थायी विजय में नहीं बदला जा सका। जीत कर भी हार जाने का यह दुर्भाग्य शायद इस ऐतिहासिक स्वातंत्र्य समर की कुण्डली में तभी लिख दिया गया था जब क्रांति का समय से पहले विस्फोट हो गया। क्षोभ के ज्वार ने विचार करने का समय न मंगल पांडे को दिया और न मेरठ के सैनिकों को ही। परिणाम की परवाह किये बिना उन्होंने हथियार उठा लिये और उनकी इस जल्दबाजी की कीमत तीन लाख से अधिक लोगों को अपना जीवन देकर चुकानी पड़ी, साथ ही दहलीज तक आ पहुंची स्वतंत्रता 90 वर्षों के लिये हाथ से खिसक गयी।

प्रथम दृष्टया इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके इसलिये यह धारणा बनी कि यह महान क्रांति असफल हो गयी। तत्कालीन शासक वर्ग के लिये भी यही अनुकूल था इसलिये उसने इसे एक असफल सैन्य विद्रोह की सीमा में ही बांधने की कोशिश की, हालांकि स्वयं उनके दस्तावेज ही अंग्रेजों के इस झूठ की कलई खोलते हैं।

1857 के स्वातंत्र्य समर जैसी घटनाएं किसी देश के इतिहास में कभी–कभी ही घटती हैं। भारत के इतिहास में भी यह अभूतपूर्व थी। अंग्रेजों की फौज में जो भारतीय नौकरी करने के लिये गये उनमें से डेढ़ लाख ने अंग्रेजों का साथ छोड़ कर भारत की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया। इनमें से एक लाख से अधिक सैनिकों ने वीर गति पायी।

ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार इस क्रांति में कम से कम चार करोड़ भारतीय सम्मिलित हुए। क्रांति के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने बड़े भूभाग में क्रांति हुई उसमें यूरोप के फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया जैसे तीन देश समा सकते थे। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध जैसे प्रमुख केन्दों सहित सैकड़ों महत्वपूर्ण स्थान तथा एक लाख वर्ग मील से अधिक भूमि अंग्रेजों को पराजित कर जीत ली गयी। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भी संघर्ष पूरी तौर पर थमा नहीं था। लगभग तीन वर्ष तक प्रत्यक्ष और बाद में परोक्ष रूप में यह संग्राम किसी न किसी तरह जारी रहा। अगले 90 वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता के लिये जो संघर्ष चला उस पर 1857 का छाया बनी रही।

सदगुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में कूका विद्रोह, जिसमें उन्होंने पंजाब के 22 जिलों में अपना शासन स्थापित कर लिया था, सैकड़ों कूकाओं ने मलेरकोट के युद्ध में बलिदान दिया तथा 68 कूका विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में विद्रोह जिसमें उन्होंने पूना के आसपास के अनेक स्थानों को अपने अधिकार में ले लिया था, द्वारा न्यायालय में दिये वक्तव्य में अपने आप को नाना साहब पेशवा का सेनापति बताना, चाफेकर बंधुओं द्वारा पूना में प्लेग कमिश्नर रैण्ड की हत्या कर उसके आतंक से मुक्ति तथा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का संचालन, गदर अखबार का प्रकाशन, भारत मुक्ति के यह सभी प्रयास 1857 के स्वातंत्र्य समर के ही अनुवर्तन थे।

1907 में 1857 के संग्राम के पचास वर्ष पूरे होने पर अवसर पर लंदन के इंडिया हाउस में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। 1857 के स्वातंष्य समर के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी, शहीदों की जय के नारे लगाये गये, 10 मई के ऐतिहासिक दिन भारतीय विद्यार्थी लंदन के बाजारों में क्रांति के बैज लगाकर घूमे।

विनायक दामोदर सावरकर ने 24 वर्ष की अल्प आयु में ही 1857 के संघर्ष से सम्बंधित डेढ़ हजार से अधिक मूल दस्तावेजों का अध्ययन कर शोधपूर्ण ग्रंथ 1857 का भारतीय स्वातंष्य समर लिखा जिस पर अंग्रेजों ने प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंध लगा दिया। गोपनीय रूप से उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशन हुआ। यह ग्रंथ क्रांतिकारियों के लिये गीता के समान पूज्य बन गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति तक भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, और खुदीराम बोस जैसे देशभक्त युवकों को यह क्रांति की प्रेरणा देता रहा।

रासबिहारी बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा उसके सेनानायक का पदभार संभालने के बाद उसके विस्तार तथा सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देने की योजना के पीछे भी 1857 की प्रेरणा काम कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस के मन पर 1857 का कितना प्रभाव था यह इस बात से ही जाना जा सकता है कि उस काल में भी उन्होंने आजाद हिन्द फौज में महिलाओं की एक पूरी रेजिमेंट बनायी तथा उसे रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया। बाद में हुए नौसेना विद्रोह के प्रेरणा स्रोत भी 1857 के स्वातंष्य समर में खोजे जा सकते हैं। ■

SFI goons killed police officer in Kerala

ABVP demands Central agency's investigation in Cop's death.

The dirty Marxist student politics of Kerala had a strange martyr on October 26. An Assistant Sub-Inspector of Changanassery police station near Kottayam, M.C. Elias (47) was killed by SFI/DYFI/CITU goondas at the NSS Hindu College in Changanassery.

The atmosphere in the College had been tense since the days of election to the College Council about a week ago when SFI activists with the support of CITU and DYFI workers were on a rampage against other student outfits. The ASI Elias, who had been isolated from the other police personnel, was trapped amidst a group of SFI students and it was then he was attacked. This is for the first time a law enforcer has been killed in student violence in the State. Police, college staff and local residents said that outside elements belonging to CPM had entered the College campus during the trouble.In all the educational institutions in Kerala where SFI is having strength no other student organisation is allowed to function. Whenever CPM comes to power, it takes its ugly turn with unleashing violence against other organisations with the connivance of State police. In all the political clashes in Kerala, the CPM is on one side and the rest on the other.

Instead of booking the real culprits, under specific directions from the State Home Minister and Marxist leader from Kannur Kodiyeri Balakrishnan, the Police took into custody several workers of ABVP/RSS/BMS/BJP and unleashed cruel methods of torture on them. Strangely, within 15 minutes of the killing, the Home Minister Kodiyeri Balakrishnan and Director General of Police Raman Srivastava said that RSS-BJP workers were behind the killing.

SFI leaders who were arrested by the Police immediately after the murder from the place of assault scene were released as instructed by the Home Minister and Kerala DGP.

The arrested workers of RSS/BJP/ABVP/ BMS were brutally tortured by the police as per the order allegedly given by CPM sympathiser DYSP Vijayan. ABVP decided to launch massive agitations, protest marches and awareness programmes across Kerala against the brutal torture of the innocent activists.

ABVP State Secretary V.P. Rajeev said SFI and the DYFI activists were responsible for the incident in the College. He too demanded a thorough probe into the incident by a Central agency. "We have no faith in the police probe," ABVP national secretary P Sandeep said.

In all the educational institutions of Kerala, frequent clashes between SFI and other student organisations is a norm thanks to the intolerant attitude of the Marxists. Police officials point out that they can do nothing since they get orders from their political bosses to side with the SFI.

Though clashes between SFI activists and other student organisations in Kerala are no news, bloodletting in such clashes had been rare in the Central Travancore region after the gruesome killing of three students belonging to ABVP by SFI-DYFI goons in the NSS Pamba College in Parumala on September 17, 1996.

Even before the Parumala killings, the NSS Hindu College, Changanassery had earned its place in murderous student politics with the killing of ABVP activist Bimbi at a commercial complex near the College about two years ago. ■

लाल झंडे के नीचे दमन की दास्तान

– कम्यूनिस्टों के राज में अशिक्षित गरीब ही नहीं, शिक्षित मध्य वर्ग भी बेबस है –

Alok Mehta

आलोक मेहता

[संपादक, आउटलुक सापताहिक]

कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ओमप्रकाश चौटाला, और लालू प्रसाद यादव शासित राज्यों से अधिक भय पश्चिम बंगाल के कम्यूनिस्ट राज में हो सकता है। पिछले सप्ताहांत कोलकाता की यात्रा के दौरान राज्य की बदतर गति तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुष की दर्दनाक बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर दमन की दास्तान सुनाने वाले प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, प्रगतिशील, विचारों वाले, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, गैर ममताई हैं इसलिए उनके तथ्यों को पूर्वाग्रही नहीं कहा जा सकता। उनके आक्रोश की पुष्टि बांग्ला भाषा के एक स्थानीय टीवी चैनल पर प्रसारित रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता महानगर सीमा क्षेत्र की एक बाहरी बस्ती के स्कूल में प्रिंसीपल ने 'मिड डे मील' योजना के तहत बच्चों को भोजन देने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त महिला कर्मचारी को इस आधार पर वापस भेज दिया वह अल्पसंख्यक समुदाय की है और उसके हाथ का खाना बच्चे कैसे खाएंगे? प्रगतिशील वामपंथी सरकार के अधिकारियों ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई के बजाए उस महिला को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के स्कूल में तनात करवा दिया। यदि यही घटना गुजरात, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश के भाजपा शासित राज्यों में हो गई होती तो हमारे जैसे कथित प्रगतिशील पत्रकार ही नहीं, केन्द्र में सत्तारूढ गठबंधन के नेता तथा दिल्ली में बैठकर राजनीति करने वाले अंग्रेजीदां कामरेड संसद को सिर पर उठा लेते। बंगाल में होने वाली घटनाओं पर लीपापोती आसान है अथवा पहली बार मिले प्रगतिशील लेखक–प्राध्यापक के अनुसार बंगाल में दमन का भंडाफोड़ करने की हिम्मत पत्रकार–लेखक नहीं जुटा सकते। यदि कोई कोशिश करता है तो कामरेड समर्थकों के पास उन्हें सबक सिखाने के पर्याप्त इंतजाम हैं।

मैने अपने ढग से थोड़ी छानबीन की कोशिश की तो सरकारी रिकार्ड से भी पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील राज की पोल खोलने वाले तथ्य सामने आए। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर केन्द्र सरकार के खंभे हिलाकर संयुक्त सेनाभ्यास के विरूद्ध सड़कों पर जुलूस निकालने वाली कम्यूनिस्ट पार्टियां अब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के मुद्दों पर आंदोलन नहीं छेड़ रहीं हैं। केन्द्र की सरकार उनकी कृपा पर आश्रित है तथा उसी सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केवल एक पहले पश्चिम बंगाल की कम्यूनिस्ट सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि चाय –बगानों में बढ रही बेरोजगारी के कारण केवल एक वर्श में 750 श्रमिकों के मौत की घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकार से पूछा गया है कि चाय–बगानों के बंद होने से बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए?

मैंने अपने ढ़ग से थोड़ी छानबीन की कोशिश की तो सरकारी रिकार्ड से भी पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील राज की पोल खोलने वाले तथ्य सामने आए। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर केन्द्र सरकार के खंभे हिलाकर संयुक्त सेनाभ्यास के विरूद्ध सड़कों पर जुलूस निकालने वाली कम्यूनिस्ट पार्टियां अब गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के मुद्दों पर आंदोलन नहीं छेड़ रहीं हैं।

हमारी प्रगतिशील सरकार के योजना आयोग की उदारवादी नीतियों की आलोचना हम अपने स्तभों, खबरों में करते रहे हैं और हमारे वामपंथी कामरेडों को तो योजना आयोग के नीति निर्धारकों के पूंजीवादी रवैये से नाराजगी

रहती है। लेकिन उसी योजना आयोग द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से कम्यूनिस्ट राज की पोल भी खुली है। कुछ अर्से पहले किए गए इस अध्ययन के अनुसार पश्चिम बंगाल में 32 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे वाली है और उसमें से 10 को तो राशन की सरकारी दुकानों से भी मुट्ठी भर अनाज नहीं मिल पाता। सब जानते हैं कि बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल मुख्य भोजन है तथा एक व्यक्ति को औसतन 550 ग्राम चावल प्रतिदिन यानी महीने में 16 किलो 500 ग्राम मिलना चाहिए। बेरोजगारी और गरीबी के शिकार लोग अपने परिवार के लिए इतने चावल का इंतजाम भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 4,612 गांवों में गरीबी रेखा नीचे वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। चाय बगान बंद होने पर गरीब परिवार सड़क पर सड़ा–गला खाना खाकर बीमारी तथा मौत के शिकार होते हैं। खाने की बात दूर रही, चाय बगान बंद होने पर प्रबंधकों की ओर से दिए जाने वाले पीने के पानी की टोटियां भी बंद हो जाती हैं। यदि मां–बाप किसी तरह मजदूरी ढूंढ़ते हैं तो उनके बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है और वे भी मजदूरी ढूंढ़ते हैं या मां–बाप के काम में हाथ बंटाते हैं। ऐसे गरीब लोगों पर कम्यूनिस्ट पार्टियों का नियंत्रण आसान होता है। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह मतदान केन्द्रों पर बटन दबाने भेजा जा सकता है। आखिरकार, सिंगुर में ग्रामीणों का विद्रोह ममता नहीं करवा सकती थीं। सिंगुर–नन्दीग्राम में तो कम्युनिस्ट मंत्री तक घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

एक और दिलचस्प बात। दिल्ली में हमारे प्रगतिशील कामरेड वर्षों से भोपाल गैस कांड को लेकर अमेरिकी कंपनी तथा वहां के शासकों की निर्ममता के विरुद्ध आग उगलते रहे हैं लेकिन भोपाल गैस कांड के लिए दोषी यूनियन कार्बाइड की मातृसंस्था बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी डाऊ केमिकल्स को हल्दिया–नन्दिग्राम में केमिकल कारखाना लगाने के लिए बंगाल की कम्यूनिस्ट सरकार न्यौता दे रही है। भोपाल गैस कांड के पीडितों का एक प्रतिनिधि मंडल दो महीने पहले कोलकाता भी पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह कैसा मजाक और दोहरा मानदंड है। आप भोपाल गैस कांड के लिए दोषी प्रबंधकों तथा पीड़ितों को मुआवजा ना देने वाले लोगों को दंडित करवाने के बजाए उनकी आरती उतारने को बेताब हैं। चीन तो दूर है, कोलकाता के बहादुर कामरेडों को लाल सलाम।

दिल्ली में हमारे प्रगतिशील कामरेड वर्षों से भोपाल गैस कांड को लेकर अमेरिकी कंपनी तथा वहां के शासकों की निर्ममता के विरुद्ध आग उगलते रहे हैं लेकिन भोपाल गैस कांड के लिए दोषी यूनियन कार्बाइड की मातृसंस्था बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी डाऊ केमिकल्स को हल्दिया–नन्दिग्राम में केमिकल कारखाना लगाने के लिए बंगाल की कम्यूनिस्ट सरकार न्यौता दे रही है।

गरीबों, मजदूरों किसानों और सिर पर मैला ढोने वालों की स्थिति अन्य राज्यों की तरह होने पर कम्यूनिस्ट मित्र सारा दोष केन्द्र की निकम्मी सरकारों को देते हों लेकिन कोलकाता का शिक्षित वर्ग भी तो प्रताड़ित और दुखी है। प्रमुख सड़कों की हालत खस्ता है, ठेकेदारों–अफसरों और नेताओं के कमीशन दिल्ली से कम नहीं ज्यादा हैं। पूंजीवाद या मार्क्सवाद का अंतर पढ़ा सकने वाले विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों में पढ़ाने के लिए बुलाए जाने अतिथि व्याख्याता को एक दिन पढ़ाने पर मात्र 150 रुपए का भुगतान होता है। औसतन एक महीने में चार बार बुलाए जाने पर एमए, पीएचडी किए व्यक्ति को 600 रुपए का भुगतान होता है। इतने पैसे में तो कोलकाता या मुजफरपुर में अशिक्षित ड्राइवर नहीं मिल सकता। घर में काम करने वाली नौकरानी इससे अधिक पैसा कमा लेती है।

प्रगतिशील कम्यूनिस्ट शासित कोलकाता में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी हिन्दीभाषी उत्तर भारतीयों की है, लेकिन उनकी स्थिति किसी रंगभेदी–नस्लभेदी देश के दूसरी श्रेणी के नागरिकों की तरह है। उनके दुख–सुख की कोई चिन्ता नहीं है। राज्य सरकार की हिन्दी अकादमी लगभग 11 वर्षों में पुनर्गठित नहीं होने से ठप पड़ी है। हां, चीन और वियतनाम से आने वाले गैर अंग्रेजी भाषियों की आरती उतारने, स्वागत द्वार बनवाने इत्यादि पर लाखों रुपया खर्च करके उन्हें सेल्यूट करते हुए कामरेडों को गौरव का अनुभव होता है। बंगाल की धरती और वहां के लोग धन्य हैं जो यह सब सहते हुए मौन हैं। ■

(साभार : आउटलुक)

महंगाई और मुद्रास्फीति का सच

-उमाशंकर मिश्र-

हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति की दर में गिरावट की घोषणा की गई थी। इस तरह की कवायदों के पीछे कुछ निहितार्थ भी छुपे होते हैं, जिन पर धूर्तता की परतें चढ़ी हुई होती हैं। मुद्रास्फीति की दर के कम होने से क्या महंगाई में भी कमी होती है एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आम आदमी नहीं सोच पाता समाचार माध्यमों की मार्फत मुद्रास्फीति में गिरावट की बात को ब्रम्हावाक्य मानते हुए आम इंसान अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात् कर लेता है। जबकि हकीकत को आंकड़ों की चादर में कुछ इस तरह से ढक दिया जाता है, मानो यही सत्य है। महंगाई के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया तो सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को कम बताकर यह बताने का प्रयास किया कि सब कुछ समान्य है। लेकिन इस बात की क्या इसी तरह से सहजता से लिया जा सकता है? अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि देश की 79 प्रतिशत आबादी की आय 20 रुपये प्रतिदिन से भी कम है। ऐसे में महंगाई के बढ़ने से क्या देश की बहुसंख्य आबादी की खाद्य सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? दूसरी ओर देश की 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इस आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जहां किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। लेकिन सरकार का ध्यान वहां नहीं जाता। बल्कि किसानों को मरता हुआ छोड़कर सरकार कार्पोरेट कंपनियों के खेमे में खड़ी हुई जान पड़ती है। जिस तरह से विदर्भ के कपास किसानों को मरता हुआ छोड़कर कॉटन मिलों को खड़ा करने की रणनीति अपनाई गई और जिस तरह से पश्चिमी महाराष्ट्र में चीनी मिलों को सब्सिडी दी जा रही है उससे सरकार का रवैया समझा जा सकता है।

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में लैपटॉप सस्ते हो रहे हैं, लेकिन आलू प्याज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, वहीं 9 प्रतिशत की विकास दर से सरकार फूली नहीं समा रही है। दूसरी ओर हमारी खाद्य निर्भरता विदेशों पर आश्रित होती जा रही है और एक बार फिर देश 'शिप टू माउथ' की स्थिति में लौटता हुआ जान पड़ता है, ऐसे में क्या इस थोथी विकास की दर से लोगों का पेट भर जायेगा?

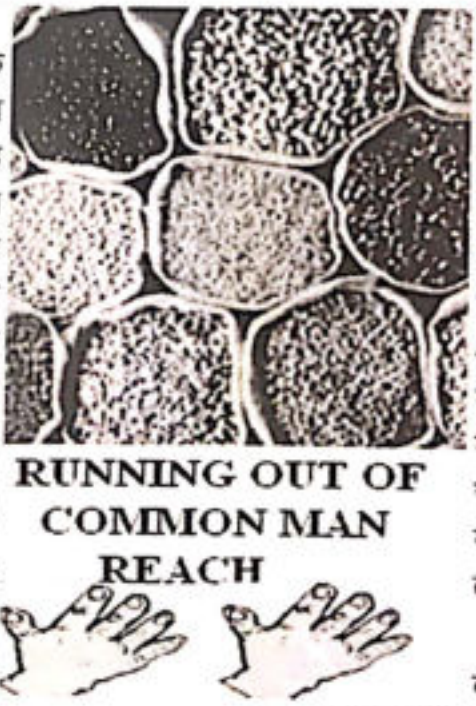

मुख्यधारा के अखबारों ने कृषि खाद्य उत्पादों की महंगाई से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी एवं अर्द्धशहरी आबादी भी महंगाई की मार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी है। देश भर की मंडियों में प्याज 28 से 35 रुपये किलो बिक रहा है तो आलू की कीमत 12 रुपये प्रतिकिलो से 18 रुपये किलो तक है। सब्जियों, फलों, ग्रोसरी और अन्य कृषि उत्पादों के दामों में वृद्धि ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया है ग्रामीण इलाकों की बहुसंख्य गरीब आबादी पहले ही प्रशासनिक उदासीनता की शिकार रही है, उस पर महंगाई की मार ने उन गरीबों का कमर तोड़ कर रख दी है।

सबसे पहले तो मुद्रास्फीति की दर को मापने वाली थोक सूचकांक की अवधारणा ही गलत है। ग्राहकों की परिस्थितियों का आकलन तभी ठीक प्रकार से हो सकता है जब सूचकांक खुदरा मूल्यों पर आधारित हों। सरकार मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठाती है। उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था में यदि पैसे का प्रवाह बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में सरकार बैंकों की ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है, जिससे लोग कम ऋण लेते हैं और प्रवाह कम

होने लगता है। जब पैसे का प्रवाह बाजार में कम हो जाता है तो इससे थोक मूल्य सूचकांक कम हो जाता है। महंगाई जब भी बढ़ती है, सरकार यही नीति अपनाकर लोगों को आश्वस्त करने का काम करती है। जबकि विशेषज्ञ इस तरह की बात को छलावे का नाम देते हैं। देविंदर शर्मा जैसे कृषि मामलों के जानकार तो इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक को भी कटघरे में खड़ा करते हुए जवाबदेही की मांग करते हैं।

सरकार ने हमेशा से ही इस तरह के मुद्दों को लेकर गोलमोल रवैया अपनाया है। महंगाई की सबसे अधिक मार गरीबों पर पड़ती है, लेकिन सरकार ने हमेशा से ही उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। 90 के दशक में जिन लोगों को 2400 कैलोरी तक भोजन प्रतिदिन मिलता था, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा गया था। लेकिन योजना आयोग ने हेर–फेर कर इस सीमा को घटाकर 1800 कैलोरी प्रतिदिन कर दिया। इसी तरह पहले करीब 278 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया था। लेकिन अब सुधार करने पर भी यह सीमा 350 रुपये तक ही पहुंच सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 350 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है? यह नहीं भूलना चाहिए कि 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेने से इस देश के गरीबों का पेट नहीं भर जायेगा। अमेरिका–परस्त सरकार को न्यूक्लीयर डील करने में अधिक दिलचस्पी है, भले ही इस डील में अमेरिका की मंशा अपने परमाणु कार्यक्रम को रिवाइव करने की ही क्यों न हो, लेकिन खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार विदेशों पर निर्भर होती जा रही है और विशेषज्ञों की मानें तो देश एक बार फिर 'शिप टू माउथ' की स्थिति में अग्रसर हो रहा है। इस तरह की खुले बाजार की नीति से क्या देश की खाद्य सुरक्षा को बचाया जा सकेगा? कार्पोरेट कंपनियों को बिचौलियों की भूमिका में लाकर खड़ा कर देने से क्या इस देश की गरीब जनता का उद्धार हो जाएगा? यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा खोते हैं राजनीतिक प्रधानता भी गंवा देते हैं।

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में लैपटॉप सस्ते हो रहे हैं, लेकिन आलू प्याज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 33 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत रह गई है। बजट में भी सिंचाई के लिए 1.3 प्रतिशत तो टेलीकॉम के लिए 13 प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है। स्पष्ट है कि सरकार देश की 60 प्रतिशत ग्रामीण जनता को उपेक्षित दृष्टि से देखती है। इन सब बातों से सरकार की दोगली नीतियां स्पष्ट हो जाती हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास दर आंकड़ों की थोथी इबारत से काम नहीं चलने वाला है सौ करोड़ लोगों के भोजन के लिए भी सोचना पड़ेगा।

सरकार नहीं चाहती कि इस देश के किसान खेती करें जिन्दा रहें। यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले करीब एक दशक में देश के करीब डेढ़ लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकारों का सामंती चेहरा नंदीग्राम की खूनी होली के रूप में सामने आता है, जहां अपनी जमीन का हक मांगने वाले किसानों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। यह इस देश की हकीकत है। सरकार यह तो नहीं करती कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाकर भूखों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करे, सरकार यह भी नहीं करती कि बेरोजगार युवाओं की भीड़ को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी हताशा को कम करने का प्रयास करे और न ही सरकार कृषि की दशा सुधारने को प्रतिबद्ध जान पड़ती है। सरकार को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डील की, जिससे उसकी अमेरिका–परस्ती बची रहे आका नाराज न हों; गेहूं तो आस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका से आयात कर ही लिया जाएगा।

अक्सर लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि आज लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। 84 करोड़ लोग जिनकी आय 20 रुपये प्रतिदिन होने की बात कही जा रही है, उनकी परचेचिंग पावर कितनी बढ़ी होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुकेश अंबानी आज बीवी के जन्मदिन पर करीब 3 अरब रुपये का उपहार दे देते है, तो दूसरी ओर देश की बहुसंख्य आबादी रोटी को मोहताज विसंगतिपूर्ण विकास का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि देश की करीब 26 प्रतिशत आबादी 9 प्रतिशत की विकास दर के बावजूद भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रही है। गरीबी रेखा का मापदंड भी सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्धारित कर लिया है अन्यथा यह आंकड़ा बढ़ भी सकता था।

सेंसेक्स के उछलते आंकड़े और विकास दर वास्तविकता बयां नहीं करते, इस देश का नागरिक जब वोट देने जाता है तो वह विकास दर नहीं रोटी, कपड़ा, मकान की बात पहले सोचता है; इसे भी उसकी अपनी ही सरकार चमकदार विकास की दमक दिखाकर आज छीन लेना चाहती है।

आजादी के 60 वर्ष
उपलब्धियां एवं चुनौतिया

सुनील कुमार बंसल
[अभाविप क्षेत्रीय संगठन मंत्री]

सन् 2007 कई मायने में महत्वपूर्ण वर्ष है 1857 स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष भगतसिंह व सुखदेव का जन्म शताब्दी वर्ष व स्वाधीनता मिले हुये 60 वर्ष पूर्ण हो रहे है। वैसे तो काल गणना में 60 वर्ष का अधिक महत्व नहीं है पर मनुष्य जीवन में व देश की सांख्यिकी में इसका विशेष महत्व है। स्वाधीनता के 60 वर्ष में हमने क्या खोया है क्या पाया है हमारी उपलब्धियां क्या है व हमारे सामने चुनौतियां क्या है इस अवसर पर इसकी चर्चा व सार्थक बहस का अपना महत्व है।

आजादी से पहले अंग्रेज कहते थे कि भारत को यदि स्वाधीन किया गया तो यह टूट जायेगा – बिखर जायेगा क्योंकि यहां पर जाति, धर्म, भाषा, भूषा के इतने सारे भेद है यह एक नहीं रह पायेगा। लेकिन हमने इन 60 वर्षो में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चलाकर दिखाया है।

पन्द्रह बार हमारे यहां आम चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके है आपातकाल के बाद आम चुनाव में लोकतंत्र का प्रशिक्षण कैसा व कितना गहरा है, इसका पता चलता है हमने जन विरोधी नीति व तानाशाही कभी स्वीकार नहीं की। आंतकवादियों की धमकी के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करता आमजन लोकतंत्र में बढ़ते विश्वास का प्रतीक है हमारे यहां सामान्य व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। देश भर में 35 लाख निर्वाचित प्रतिनिधी है, जिसमें से 13 लाख महिलायें हैं। विश्व में कहीं पर भी इतनी निर्वाचित महिला प्रतिनिधी नहीं है।

स्वाधीनता के समय 7 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था आज हम खाद्यान्न के मामलों में आत्म निर्भर है। आज विश्व का सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश हमारा है। आजादी के बाद शिक्षा का विस्तार गांवों तक हुआ है। आजादी के समय 20 विश्वविद्यालय थे आज 250 से अधिक है। 10,000 से अधिक महाविद्यालय व 30,000 हजार सीनियर विद्यालय है। 1951 में साक्षरता दर–18.33 प्रतिशत थी जो 2001 में 64.8 प्रतिशत हो गई है। लाखों – इंजीनियर डॉक्टर प्रतिवर्ष हम तैयार कर रहे है। शिक्षा की बदौलत ही प्रतिभा के मामले में आगामी पांच वर्षो में हम विश्व के 10वें स्थान पर होंगे।

लाखों – इंजीनियर डॉक्टर प्रतिवर्ष हम तैयार कर रहे है। शिक्षा की बदौलत ही प्रतिभा के मामले में आगामी पांच वर्षो में हम विश्व के 10वें स्थान पर होंगे। तकनीकी क्षेत्र में आज हम मिसाइल व सैटेलाइट का निर्माण कर रहे है। क्रायोजेनिक इंजन व सुपर कम्प्युटर हमने बना लिया है हमारी रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है, दिल्ली मेट्रो रेल विश्व की बेहतरीन सेवा है, 20 करोड लोगों के पास फोन सुविधा है। आई.टी. क्षेत्र में हम 31.4 करोड़ डालर का निर्यात कर रहे है।

तकनीकी क्षेत्र में आज हम मिसाइल व सैटेलाइट का निर्माण कर रहे है। क्रायोजेनिक इंजन व सुपर कम्प्युटर हमने बना लिया है हमारी रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है, दिल्ली मेट्रो रेल विश्व की बेहतरीन सेवा है, 20 करोड लोगों के पास फोन सुविधा है। आई.टी. क्षेत्र में हम 31.4 करोड़ डालर का निर्यात कर रहे है।

खेल के क्षेत्र में फुटबाल में नेहरू कप, हॉकी में एशिया कप, 20–20 क्रिकेट में विश्व कप, शतरंज बिलियर्डस व अन्य खेलों में भी आगे बढ़ रहे है। चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण व्यक्ति की औसत आयु 63 वर्ष हो गई है

क्योंकि हम बेहतर व सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करा रहे है।

विश्व की 12 बड़ी अर्थव्यवस्था में हम आ चुके है। हमारी आर्थिक विकास दर 1950 में 3.5 थी आज 2007 में 9.4 है। हम विदेशी कम्पनियों का अधिग्रहण कर रहे है। सामाजिक दृष्टि से जातीय विषमता की खाई कम होती दिखाई दे रही है। अपने परम्परागत क्षेत्र–योग, आयुर्वेद, संस्कृत भाषा के क्षेत्र में भी इन 60 वर्षो में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे है।

स्वाधीनता के 60 वर्ष में हमारी इन उपलब्धियों के साथ–साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही है।

आर्थिक विकास के इस दौर में देश में अमीर व गरीब का भेद बढ़ रहा है व गांवों से पलायन बढ़ रहा है। क्योंकि वहां परिश्रम अधिक व सुविधायें कम है जिसके कारण शहरों में कच्ची बस्तियां बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के दबाव के अनुरूप शहरों में सुविधाओं का अभाव आज हमारे सामने एक चुनौती बन कर खड़ा है।

बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण–पैसे के लिए सब कुछ करने की मानसिकता ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रभाव डाला है। हमारी प्रवृति व कार्य संस्कृति बदल रही है। मनुष्य मशीन के रूप में काम कर रहे है। सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो रहे है व्यक्ति का शोषण बढ़ रहा है।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बढ़ता हुआ तुष्टीकरण अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है स्वाधीनता के साथ हुआ विभाजन इसी का परिणाम था। आज फिर वोट बैंक की राजनीति के नाम पर इस प्रकार की मानसिकता के कई उदाहरण हमारे सामने है। एक वर्ग को खुश रखने के लिए दूसरे वर्ग का बार–बार अपमान करना क्या ठीक है। देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो यह मानसिकता देश में बनाने की आज आवश्यकता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षा के निजीकरण के नाम पर बढ़ता व्यापारीकरण, देश में बढता आतंकवाद व नक्सलवाद समाज में शिष्टाचार के रूप में स्थापित हो चुका भ्रष्टाचार, समाज की संघर्ष करने के बजाय समझौतावादी मानसिकता जैसी कई चुनौतियां व समस्यायें इन 60 वर्षो में हमारे सामने आई है जिनसे भी हम सब को लड़ना व संघर्ष करना है।

इन सब उपलब्धियों व चुनौतियों के साथ देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी कुछ भूमिका भी बनती है क्योंकि देश व समाज के प्रति संवेदना का भाव होने पर ही कुछ कर गुजरने का मन बनता है।

भावी पीढ़ी में देशभक्ती, मातृभक्ति भाव का स्थायी निर्माण, राष्ट्र प्रथमव सर्वोपरी है इस प्रकार की मानसिकता बनाने के लिये कार्यक्रमों की योजना व रचना करना, हमारी सामाजिक परम्परागत व्यवस्थाओं को मान्यता व बढ़ावा देना, समय के साथ सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाना, भारत एक ज्ञान आधारित समाज था –अपने परम्परागत उस ज्ञान को सम्मान देना – अध्ययन करना, शोध करना व स्वाभिमान के साथ खडे होना, सम्पूर्ण देश में व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करना, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना।

"इन्डिया कैन नाट डू क्लब" भारत कुछ नहीं कर सकता– इस क्लब की मानसिकता से बाहर आकर अपनी सभ्यागत कमजोरियों को छोड़कर समाज की कुरीतियों को दूर करते हुये अपनी संस्कृति व स्वाभिमान के साथ कल के भारत का निर्माण करना यह हम आज युवाओं की भूमिका है। ■

विरासत की वापसी की व्यथा

जाने माने कानूनविद् और पूर्व सांसद लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का 6 अक्टूबर, दिन शनिवार को निधन हो गया। सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे श्री सिंघवी का जन्म राजस्थान के जोधपुर में वर्ष 1931 में हुआ। श्री सिंघवी कानूनविद के अलावा संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद् और प्रखर लेखक थे। वह कई कला एवं सांस्कृतिक संगठनों के संरक्षक थे। वर्ष 1962–67 तक वे तीसरी लोकसभा के सदस्य रहें। वर्ष 1972–77 तक वे राजस्थान में महाधिवक्ता रहे। उन्हें वर्ष 1998 में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में राज्यसभा के सदस्य बने। श्री सिंघवी अनिवासी भारतियों की उच्चस्तरीय समिति के सदस्य भी रहें। जैन इतिहास और भारतीय संस्कृति के जानकार श्री सिंघवी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं। जिनमें कुछ हिन्दी में भी है। छात्रशक्ति के इस अंक में प्रस्तुत है साप्ताहिक हिन्दी 'आउटलुक' में प्रकाशित उनका एक लेख। जिसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि श्री सिंघवी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे हों, वह अनाधिकारिक रूप से भारत के सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर ही रहे हैं।

लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

महात्मा गांधी की हत्या के उन्नीस दिन पूर्व 22 जनवरी के दिन हरिजन के लिए लिखी बापू की संपादकीय टिप्पणी की नीलामी को लेकर चल रही राजकीय गहमा–गहमी को देखकर वे कई संस्मरण मेरे समक्ष चलचित्र की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं जो साक्षी हैं हमारी विरासत की व्यथा–वेदना और अमूल्य धरोहर की वापसी के, जिन्हें लाने में मैं भारत निमित्त बना। सन् 1991 में मुझे राजदूत पद ग्रहण किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा कि अचानक एक दिन सुबह के अखबार में बारीक अक्षरों में एक विज्ञापन देखा। जिसमें सूचना थी कि टैगोर पेपर्स की नीलामी होने वाली है। मेरी पत्नी ने कहा– 'गुरुदेव के ये हस्तलिखित दस्तावेज आपको अवश्यमेव भारत ले जाने चाहिए।' प्रो. विलियम राडिचे जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ने कहा, 'गुरुदेव के लिखे ये 468 पृष्ठ अपने वजन की तोल के हजार गुना अधिक बशकीमती है।' मैंने पाया कि यह तो गुरुदेव का अद्भूत–अपूर्व खजाना था। मैंने सरकार को लिखा। सरकार ने इस मामले में अपनी वित्तीय विवशता जताई। मेरी पत्नी ने कहा, 'मैं अपने जेवर और जमीन बेच दूंगी किन्तु गुरुदेव की हस्तलिखित यह पांडुलिपियां भारत लौटनी ही चाहिए अन्यथा आपका राजदूत होना गर्व की बात नहीं मानी जाएगी।' उधर, यह खबर आई कि बेकन नाम के एक बड़े अंग्रेज धनपति ने वे कागजात खरीदने का संकल्प कर लिया है। मुझे डर था कि हम ऐसे बड़े धनपति के सामने नहीं टिक पाएंगे किन्तु संयोगवश बेकन मेरे मित्र बन गए और उन्होंने ही मुझे सबसे बड़ी मदद की। जब वे बहुमूल्य कागजात मैंने मुख्यमंत्री ज्योतिबाबू को भेंट किए तो उन्होंने कहा, 'अब तक हम आपको बंगाल का जमाई बाबू कहा करते थे, अब हम कहेंगे कि गुरुदेव के प्रति आपका आगाध प्रेम आपको एक मानद बंगाली की श्रेणी में सम्माननीय आसन का अधिकारी बनाता है।'

विरासत का एक दूसरा प्रकरण तमिलनाडु से तस्करी द्वारा चुराई हुई नटराज मूर्ति एवं 228 कलाकृतियों का है। उन मूर्तियों और कलाकृतियों को एक मल्टीनेशनल ने खरीद लिया था। उच्चायोग ने मुकदमा दायर किया किन्तु हमें यहां साबित करना जरूरी था कि यह मूर्तियां भारत से ही चुराई गई थीं। भारत की धरती की मूर्ति पर पड़ी धूल में पड़े सूक्ष्मतम कीटाणुओं का भारतीय उद्भव साबित होने पर नटराज की वह अमूल्य मूर्ति और साथ की कलाकृतियां हमें मिल गईं। इस मूर्ति की कीमत आज कई करोड़ रुपए है। केस जीतने पर भी प्रतिमा और कलाकृतियों को हस्तगत करने के लिए मुझे पूरा कानूनी व्यायाम करना पड़ा। फिर खबर आई कि महात्मा गांधी की अपनी श्रीमद्भगवत गीता की भी नीलामी होने को है। मेरे मित्र भारतवंशी माधवानी जानते थे कि मैं गांधी जी की गीता भारत के लिए हासिल करना चाहता था। मेरे जन्मदिन के दिन मित्रवर मनुभाई माधवानी गांधी जी की गीता की वह प्रति नीलामी

में खरीद कर मुझे भेंट करने मेरे राजकीय निवास पर आए। उस शाम कैंटरबरी के आर्कबिशप, ब्रिटेन के चीफ रब्बाई इत्यादि मेरे साथ भोजन पर आमंत्रित थे। मनुभाई ने कहा– 'गांधीजी की यह गीता आपको आपके जन्मदिन पर भेंट कर रहा हूँ।' मैंने कहा, 'हमारे इस पवित्र पारंपरिक ग्रंथ को अपने लिए नहीं बल्कि भारत की ओर से भारत के लिए स्वीकार कर रहा हूं।' मैंने गांधीजी की गीता की वह प्रति राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा को भेंट की।

विरासत की व्यथा और वापसी का सबसे कठिन और विकट मामला था गांधीजी के अगणित पत्रों का, जिसे उनका टाइपिस्ट (वी. कल्याणम्) उनकी हत्या के बाद बिना किसी स्वत्वाधिकार अपने सूटकेस में लेकर चला गया। कालांतर में कल्याणम् एक अमेरिकी मूल के हिन्दू सन्यासी शिवाय सुब्रहमनिया से मिला और उनको वे सारे दस्तावेज दे दिए। सन्यासी शिवाय उन बहुमूल्य कागजों को लंदन में बेचकर हवाई द्वीपों में एक शैव मन्दिर बनाना चाहते थे क्योंकि ऐसी पांडुलिपियों का बड़ा वैश्विक बाजार अमेरिका में नहीं, ब्रिटेन में है। उन्होंने वे कागजात फिलिप्स नाम की कंपनी को नीलामी के लिए दे दिए। मैंने जब यह पता लगाया कि किस प्रकार वे कागजात नीलामी के लिए लंदन पहुंचे तो सारा किस्सा मालूम हुआ। मैने सोचा कल्याणम् से बात करने से शायद बात सुधर जाए। मेरे राजदूतावास में वरिष्ठ सांस्कृतिक अधिकारी और मेरे अनुज समान गोपाल कृष्ण गांधी ने बहुत प्रयत्न किया पर कल्याणम् हठी था और अहंकारी भी। मैंने हिन्दू समाचार पत्र के वर्तमान संपादक एन. राम की मदद ली। विश्लेषण किया तो लगा कि यह चोरी का माल था। जिस पर कल्याणम्, सन्यासी शिवाय या फिलिप्स कंपनी का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था। यह खोजने में कि गांधीजी के दस्तावेजों पर नवजीवन ट्रस्ट को सर्वाधिकार किस किस दस्तावेज से मिला। हमें महात्मा गांधी की वसीयत का प्रारूप मिल गया। तत्काल मैने राम लाल गांधी से संपर्क किया। गांधी जी की वसीयत की प्रोबेट मंगवा ली और फौरन फीलिप्स कंपनी को एक कानूनी नाटिस जारी किया। इधर हाउस ऑफ कामन्स में एक निजी प्रस्ताव भी आया कि उच्चायुक्त विरासत के ये दस्तावेज पाने के अधिकारी हैं। गार्जियन पत्र ने विशेष दो पृष्ठ भी छापे। मैंने अपने ब्राडकास्ट में कहा कि भारतीय विरासत के ये दस्तावेज चुरा कर लाए गए थे और फिलिप्स कंपनी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी को यह शोभा नहीं देता कि वह चुराए गए दस्तावेज की नीलामी करे। नीलामी नीरस्त हुई। फिलिप्स ने सारे कागज सविनय मुझे लौटा दिए। कंपनी कई लाख रुपए भुगतान कर चुकी थी किंतु वह भी उसे ही भुगतना पड़ा। ये करोड़ों रुपए मूल्य के कागजात आज नेहरू संग्राहलय में ही सुरक्षित हैं।

मेरे मित्र भारतवंशी माधवानी जानते थे कि मैं गांधी जी की गीता भातर के लिए हासिल करना चाहता था। मेरे जन्मदिन के दिन मित्रवर मनुभाई माधवानी गांधी जी की गीता की वह प्रति नीलामी में खरीद कर मुझे भेंट करने मेरे राजकीय निवास पर आए। उस शाम कैंटरबरी के आर्कबिशप, ब्रिटेन के चीफ रब्बाई इत्यादि मेरे साथ भोजन पर आमंत्रित थे।

मामले की शुरूआत में मैंने एक पत्र सन्यासी शिवाय को लिखा था– उनसे मेरा अच्छा परिचय था। मैंने उनको लिखा था कि एक पवित्र हिन्दू मन्दिर की नींव में चोरी से पाया गया धन या द्रव्य नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिवस पर अपना शुभाशीष और शुभाशंसा देते हुए फैक्स द्वारा लिखा कि आज मैंने हिन्दू परंपरा का एक गहरा और पवित्र सबक आपसे सीखा है। फिर भी मेरी पत्नी के मन में यह मलाल था कि मेरे कारण मंदिर का काम रुका इसलिए उन्होंने हवाई मंदिर के लिए छोटा सा द्रव्य स्वामीजी को भेजा। मेरे मन में किन्तु कोई अपराध बोध नहीं था क्योंकि भारत के अनमोल विरासत के लिए जो मैंने किया वह मेरा प्रथम एवं पुनीत कर्तव्य था।

मेरे मित्र भारतरत्न डा. अब्दुल कलाम ने विशेषतया टीपू सुल्तान के रॉकेट को भारत ले आने की पेशकश भी की थी किन्तु तब वह संभव नहीं हो पाया। विश्व के कई संग्राहलयों में भारत की विरासत के अगणित प्रतीक चिन्ह उपनिवशवादी प्रभुत्व के समय बाहर ले जाए गए। आज भी विरासत की यह व्यथा और वेदना मन को आकुल और व्याकुल करती है, किन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि पश्चिम के कई संग्राहलयों में हमारी संस्कृति की धरोहर का रखरखाव संतोशजनक है एवं उत्साहवर्धक है। क्या प्रवासी भारतीय सन्नद्ध और इस अभियान में भारत सरकार के साथ जुड़ेगे?

भारत में अल्पसंख्यक कौन ?

Sri K.S. Sudarshan

Sarsanghachalak of RSS in his Vijayadasami speech in 2003.

"Let us raise the fundamental question as to who should be called a minority? In reality Minorities are those who migrate from other countries and settle here. In that sense only the Jews and Parsis fall under the category of minority. But they refused to call themselves as minorities and fully integrated themselves in the national mainstream. 99% of the Muslims and 99.9% of the Christians in India have not come from outside. They belong to this land only. They might have changed their religion a few generations ago, but how come that makes them minorities?

There is complete freedom of worship in this land because the Hindus believe that truth is one while the learned call it by different names and all those different paths to realise that truth are also equally true. Therefore mere change of religion does neither change one's motherland nor the ancestors. Hence those who are being categorised as minorities today must take a stand that they are not minorities and they are an integral part of this national society."So, should there be minority-majority differentiation in India?

नाजिया आलम खान, बरेली

जैसा कि मेरा सोचना है कि विश्व में सर्वाधिक अल्पसंख्यक भारत में रहते है तो दूसरी और यह भी सोचना है कि हमारे यह अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि हो रही है यह एक लम्बे समय तक चलने वाला मुद्दा है और पर धार्मिक वृद्विजीवियों व राजनेताओं तथा कानून के ज्ञाताओं द्वारा अलग–अलग तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता है। परन्तु वास्तविकता का द्वार खोलने से सभी कतराते हैं। आखिर सच और उसके प्रमाण क्या है। 26 जनवरी, 1950 से आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया है। कि अल्पसंख्यक कौन है? लेकिन निर्णय भविष्य पर छोड़ दिया गया। अल्पसंख्यक को से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार किया जाये तथा एक जनमानस तैयार किया जाये कि हम भारत के लोग अल्पसंख्यक जैसे मुख्य विषय को इस प्रकार से निर्मित करें जिससे इस देश को अखण्डता सुनिश्चित हो सके एवं वह विश्व बन्धुत्व की भावना के विपरीत न हो।

यह पूर्व विदित है कि जब संविधान सभा में जो बहस चली थी कि5 प्रतिशत ज्यादा आबादी वाला समुदाय उस स्थान विशेष में अल्पसंख्यक नहीं है।अभी हाल में 4 अप्रैल, 2006 को उत्तर प्रदेश में मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में 89 पृष्ठ का विस्तृत फैसला सुनाया कि 1951 की जनगणना व 2001 की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता हैकि अल्पसंख्यकों की आबादी में वृद्धि हुई है यही वहीं राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर है इसी बात से पता चलता है कि 18 सांसद 54 विधायक व 9 विधान परिषद सदस्य हैव। इन सबके अतिरिक्त अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर जो लाभ उन्हें दिये जाते है वह अलग हैं। इतनी साफ तस्वीर होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं किया जाता है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि उन्हे देश का मुख्य धारा में शमिल होने से रोकने समान नागरिक संहिता का उल्लघन करने और भेदभाव की नीति को बढ़ावा देने का कार्य संकुलरवादी कर रहे है। ■

परिचर्चा

पश्चिम में धुलती हिंदी भाषा

इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। अधिक से अधिक 500 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ 25 जनवरी तक प्रेषित करें। प्राप्त उत्तर जनवरी– फरवरी अंक में प्रकाशित किये जायेंगे।

सम्पादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति
136, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001

OBITUARY

Shri J P Mathur

Mathurji, who was ailing for sometime, was hospitalised on October 8, 2007, and he breathed his last on October 20 at 5:00 am at Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. He was 86.

Mathurji joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh in 1942 and became a pracharak in 1945. With the blessing of Shri Guruji, Mathurji worked with senior RSS leaders like Dattopant Thengadiji, Chamanlalji, Sunder Singh Bhandariji, and Kushabhau Thakreji and remained a bachelor all his life. He became member of Bharatiya Jana Sangh in 1952. He was office secretary of the central office of Jana Sangh for a long period. He also served as national secretary of Jana Sangh. Mathurji was also one of the founder members of the BJP and remained a member of the national executive of the party till the end. He also held the responsibility of BJP's national secretary, national vice president and national spokesperson.He was the Deputy Leader of BJP Parliamentary Party in the Rajya Sabha in 1993. He left an indelible mark as a parliamentarian. He was elected to the Rajya Sabha in April 1978 and again in April, 1990. He was the Chief Whip in 1990.

A social and political worker Mathurji participated in "Quit India" Movement in 194[illegible] He also participated in the Kashmir Movement in 1953 which was led by Dr. Syama Prasad Mookerjee. When Emergency was imposed in the country he worked underground from June, 1975 to March, 1977. He handled foreign publicity and carried a prize over his head by the Delhi Police for arrest.

Mathurji, despite holding many high posts in the party, was a true swayamsevak, committed to Sangh ideology. Mathurji lived a disciplined life and served the country till his death. He was devoted to the nationalist cause and dedicated his entire life in service to the nation.

Shri S.S. Bajwa

Delhi's Deputy Mayor S S Bajwa died in New Delhi on October 21 of head injuries after falling from the terrace of his house following an attack by monkeys. The 52-year-old Corporator from Anand Vihar ward was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) of Apollo hospital a day earlier with multiple injuries and his condition deteriorated later leading to his death.

A businessman by profession and Delhi BJP Vice-President, Shri Bajwa, was walking on the terrace of the first floor of his house when the monkeys attacked him after which he lost balance and fell from terrace at around 8 AM.

Bajwa was elected to the Municipal Corporation of Delhi for the first time in April this year. He is survived by a wife and a son.

कहीं देर न हो जाए

- आशीष कुमार 'अंशु'-

भारतीय समाज प्रारंभ से अपने मूल्यो और संस्कारों को महत्व देने वाला रहा है, यह समाज अपनी सहिष्णुता की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, यह देश बुद्ध, महावीर, विवेकानन्द और गांधी का है। मगर हमारे संयम को कुछ लोग कायरता समझ बैठे हैं। जिस वजह से एक–एक करके हमारे मूल्यों, आस्थाओं और परंपराओं को नष्ट–भ्रष्ट करने की कोशिशें तेज हो गई है। यदि इस वक्त हम नहीं संभले तो हो सकता है कि जब हमारी नीन्द खुले तब तक काफी देर हो चुकी हो।

इस साल के अन्तिम महीनों कें आसपास दो ऐसी घटनाएं हुई जिसकी नोटिस समाज और मीडिया ने कम ली लेकिन इस वजह से हम इन घटनाओं की गंभीरता को कम करके नहीं देख सकते।

पहली घटना राजधानी स्थित केन्द्रिय अनुदान पर चलने वाली प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की है। जिसने भगोड़े चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को– वास्तव में जिसे चित्रकार कहना कला का अपमान करना होगा – सम्मानित करने का फैसला लिया। जो व्यक्ति भारत आने से डरता है, जिस व्यक्ति पर देश भर में 9 मुकदमें दर्ज हैं, जो देश के बाहर लन्दन में तड़ीपार की जिन्दगी जी रहा है, जो अपनी गिरतारी के डर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि लेने जामिया में हुए अपने सम्मान समारोह में नहीं आया। उसे अभी यह उपाधि देकर सम्मानित करने की विश्वविद्यालय को क्यों सुझी? जबकि वह देश से निर्वासित है। यह सम्मान उसे देश वापसी के बाद भी तो दिया जा सकता था? कितने शर्म की बात है, केन्द्रिय अनुदान पर चल रहे विश्वविद्यालय में एक अपराधी को सम्मानित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम कोई गुपचुप तरीके से नहीं हुई। बकायदा पहले इसकी घोषणा की गई। 30 अक्टूबर को हुए सम्मान समारोह वाले कार्यक्रम में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद जी अंसारी भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ही हुसैन के सम्मान में कसीदे पढ़ते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि – 'हुसैन हमारे समय के सबसे सम्मानित कलाकार हैं।'

हुसैन ने मां दुर्गा की सिंह के साथ नंगी तस्वीर बनाई, लक्ष्मी जी की नंगी तस्वीर बनाई, जिसमें वह गणेश जी के सिर पर बैठी हैं। देवी सरस्वति की वीणा के साथ नग्न तस्वीर बनाई, उसने भारत माता की नग्न तस्वीर बनाई। इन अपराधों के लिए उसे जितनी सजा दी जाए कम है। मगर उसे सम्मानित किया जा रहा है। वह भी कहीं और नहीं, इसी देश में। उसके समर्थक कहते हैं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं यह जानना चाहता हूं, उसकी यह स्वतंत्रता अपनी मां शाहीन का चित्र को बनाते समय कहां चली गई थी? यह किसी ने उससे नहीं पूछा। वह तो सिर्फ एक व्यक्ति की मां है। जिसका उसने इतना ख्याल किया। लेकिन दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों भारतीयों की आस्था का उसने जरा भी ख्याल नहीं रखा। क्या मकबूल से पूछकर मुझे कोई बताएगा कि जिस तरह की तस्वीर वह हिन्दू देवी–देवताओं की बनाता है, वैसी तस्वीर कोई चित्रकार उसके पुत्री की बनाए तो क्या ऐसी तस्वीर बनाने की वह (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर) उसे छुट दे देगा, या

हिन्दू समाज का अभी भी सद्भाव में विश्वास है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में शर्म की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को इस देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में सम्मानित करता है और इस देश की मीडिया और आम जनता इस पूरे प्रकरण को तमाशबीन की तरह देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती।

फिर वह इतना निष्पक्ष चित्रकार है तो क्यों नहीं उसने ऐसी एक तस्वीर मोहम्मद साहब की बनाई? इसकी वजह मुझे सिर्फ इतनी जान पड़ती है कि वहां खुमैनियों और फतवाओं की परंपरा है। हिन्दू समाज का अभी भी सद्भाव में विश्वास है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में शर्म की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को इस देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में सम्मानित करता है और इस देश की मीडिया और आम जनता इस पूरे प्रकरण को तमाशबीन की तरह देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती।

कंडोम वितरण और सेक्स एजुकेशन के माध्यम से कहीं न कहीं हमारे मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है। बिन्दास बोल हमारे देश में वाया कंडोम सेफ सेक्स का पश्चिमी पैटर्न लाने की साजिश है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि यह हमले का पूर्वाभ्यास है। यदि इस वक्त हम खामोश रहें तो हो सकता है, जब तक हम संभले तब तक काफी देर हो चुकी हो।

अब बात करते हैं दूसरी घटना की, इसी साल 06 नवम्बर को लन्दन में 'अन्तरराष्ट्रीय जनसंपर्क एजेन्सी' और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार एक भारतीय जनसंपर्क एजेन्सी 'कारपोरेट वाइस/वेबर शैंडवीक' को 'आईपीआरए गोल्डन अवार्ड' से सम्मानित किया गया। भारत में कंडोम की बिक्री बढ़ाने के लिए इसने एक नायाब तरीका ढूंढ़ा। यह तरीका था, 'बिन्दास बोल–कंडोम बोल' के विज्ञापन का। आपने भी यह विज्ञापन जाने–अंजाने में देखा होगा। इस कैम्पेन में कंडोम की बिक्री करने वाली दुकानों पर कुछ उपहार की व्यवस्था की गई थी। यदि ग्राहक बिना किसी संकोच के दुकान पर आकर कंडोम की मांग करता था, तो उसे दुकानदार पुरस्कार देते थे। यह कैम्पेन हिट हुआ और कंडोम के भारतीय बाजार में 22 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जिन 08 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को केन्द्र में रखकर यह कंडोम कैम्पेन चलाया गया। वहां वृद्धि 45 फीसदी रही। प्राइवेट सेक्टर पार्टरनरशिप फार बेटर हेल्थ (पीएएस – वन), यूनाइटेड स्टेट एजेन्सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) प्रोजेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वेबर ने अपना कैम्पेन भारत में चलाया। यहां पुरस्कृत होने की बात यह नहीं है कि कंपनी ने कंडोम की बिक्री बढ़ा दी। कमाल की बात तो यह है कि उसने यह कारनामा भारत जैसे देश में कर दिखाया। जहां संस्कृति, संस्कार, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का हमेशा सम्मान किया जाता रहा है।

कंडोम वितरण और सेक्स एजुकेशन के माध्यम से कहीं न कहीं हमारे मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है। बिन्दास बोल हमारे देश में वाया कंडोम सेफ सेक्स का पश्चिमी पैटर्न लाने की साजिश है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि यह हमले का पूर्वाभ्यास है। यदि इस वक्त हम खामोश रहें तो हो सकता है, जब तक हम संभले तब तक काफी देर हो चुकी हो। ■

"Proud to be from an RSS family"

-Sunita Williams

NASA astronaut Sunita Williams said while addressing a Rotary Club function in Ahmedabad in the presence of her father, thus: "When I landed up in naval academy I had to adjust to military discipline. The RSS culture of discipline in our family came in handy for me at that stage since my father had been associated with the RSS."

While addressing a meet under the aegis of the Ahmedabad Management Association she also spoke on Ram Sethu. She said : "I took pictures of the bridge between India and Sri Lanka from the space station." Sunita Williams, whose father Dr. Deepak Pandya hails from Gujarat, arrived in Ahmedabad on a week-long visit to India.

मुलाकात

बी. सुरेन्द्रन
(सह संगठन मंत्री)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री बी.सुरेन्द्रन से शिक्षा, रोजगार सांस्कृतिक मूल्यों एवं वर्तमान मुद्दों के संदर्भ में 'उमाशंकर मिश्र' द्वारा की गई बातचीत के प्रमुख अंश-

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं, यह कितनी प्रभावकारी है, क्या एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए?

शिक्षा के साथ व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाने का मूल विषय जुड़ा हुआ है, जो शिक्षा के वर्तमान स्वरूप से पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षित होकर भी बेरोजगार रह जाती है, यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है। एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए तीन प्रकार के बदलावों की जरूरत होगी। पहली बात तो यह ध्यान में रखनी होगी कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाय, जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण, जिससे अधुनातन ज्ञान–विज्ञान को बढ़ावा मिल सके, जो जीवन को आसान एवं बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने की है, वह है– शिक्षा में नैतिक, सामाजिक मूल्यों का समावेश; जो नई पीढ़ी को न केवल संस्कारवान बनाने का कार्य करती है, बल्कि अपनी विरासत के संरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

बात अगर शैक्षिक सुधारों की करें, तो सबसे बड़ी जरूरत आज पाठ्यक्रमों को नये सिरे से तैयार करने की है, जिससे परंपरागत विशयों को अधिक रोजगारपरक बनाया जा सके। जैसे कि इतिहास के साथ पुरातत्व विज्ञान, हिन्दी भाषा के साथ जनसंचार; इस तरह से कोर्स तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना है कि सरकार का इस तरफ ध्यान नगण्य है। हालांकि विद्यार्थी परिषद् जैसे संगठनों ने समय–समय पर सरकार को चेताया है और यूजीसी को भी इस निमित्त प्रस्ताव भेजा है।

गैट्स क्या है और आम छात्र को इसके निहितार्थों एवं खतरों को कैसे समझाया जा सकता है?

बड़े सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि, गैट्स के लिए दरवाजे खोल देने से शिक्षा का बाजारीकरण हो जाएगा, जो जितना अधिक पैसा देगा, उसे उतनी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा व्यवस्था एक सुपर बाजार की तरह हो जाएगी, जिसके पास पैसा है वह उच्च दर्जे की शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसके पास पैसा कम होगा वह निम्न दर्जे की शिक्षा हासिल कर पाएगा। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वह बस उस सुपर बाजार से घूमकर वापस लौट आएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति विकराल रूप धारण कर लेगी, जिससे अराजकता, अशांति बढ़ेगी तथा सामाजिक समरसता ख़तरे में पड़ जायेगी।

सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों की बजाय बड़ी परियोजनाओं, कार्पोरेटाईजेशन और विकास की दर की ही चिंता में ग्रस्त रहती है; आज क्या नेहरू के विकास के मॉडल की समीक्षा की जरूरत है?

बिल्कुल आज नेहरू के विकास की मॉडल की समीक्षा की आवश्यकता है। उस समय की परिस्थितियां तीव्र गति से विकास की थीं, लेकिन आज की स्थिति भिन्न है। वर्तमान विकास के मॉडल से, गरीब, किसान, आदिवासी, पिछड़ों तथा मजदूरों की स्थिति बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 60 प्रतिशत आबादी जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, आज त्राहि त्राहि कर रही है। 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था का लाभ मुट्ठी भर लोगों को हो रहा है। ऐसे में शहरी एवं ग्रामीण तथा गरीब तथा अमीर के बीच खाई बढ़ रही है। यह विसंगतिपूर्ण विकास

है। भारत को आर्थिक सत्ता बनाने के लिए निचले स्तर से सोचना पड़ेगा, जिससे गरीबों, ग्रामीणों, किसानों, पिछड़ों तथा आदिवासियों के हित सुरक्षित रह सकें और तभी गांव पुनः पूर्ण सत्ता बन सकेंगे।

रामसेतु जैसे आस्था के प्रतीक को विवादास्पद बनाये जाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

रामसेतु निर्विवाद रूप से इस देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था से जुड़ा हुआ प्रतीक है। इसके वर्तमान विवाद को लेकर मैं 4–5 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि आस्था की इस धरोहर को तोड़े जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने और खिलवाड़ करने का अभाविप विरोध करती है। दूसरा प्रश्न रामसेतु को तोड़ जाने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इसके तोड़े जाने से और वहां से जहाजों के गुजरने से मछलियां वहां से दूर चली जाएंगी। ऐसे में मछुआरों को मछली पकड़ने के अंतराष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करना होगा, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में 16 लाख मछुआरों के समक्ष जीवन यापन का संकट आन पड़ेगा। तीसरा प्रश्न पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जहां सेतुसमुद्रम परियोजना बनाने की बात की जा रही है, वह क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कहलाता है, जहां दुनिया की सबसे अधिक करीब 3,500 बायोडायवर्सिटीज पाई जाती हैं। इस परियोजना के कारण इस जैव विविधता का अस्तित्व संकटग्रस्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले केन्द्र सरकार ने ही 100 करोड़ रुपये की राशि इसके संरक्षण के लिए आवंटित की थी, लेकिन आज वही सरकार इसको समाप्त करने पर तुली हुई है। चौथा बिन्दु सुनामी जैसी प्रकृतिक आपदाओं से संबंधित है। रामसेतु तोड़े जाने के कारण रास्ता खुलने से विद्युतीय तरंगों में बदलाव आएगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में सुनामी जैसी प्रकृतिक आपदाओं से दक्षिण भारत के दो प्रांत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पांचवा विषय रामसेतु के तोड़े जाने से थोरीयम के विशाल भंडारों के नष्ट होने से संबंधित है, जिससे आगामी 350 वर्षों तक उर्जा की उत्पादन किया जा सकता है। रामसेतु के तोड़े जाने से यह भंडार भी नष्ट हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की समीक्षा की जरूरत है।

अभाविप फिलहाल किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है?

अभाविप वर्तमान समय में मुख्य रूप से तीन तरह के मुद्दों के लेकर अग्रसर है। पहला विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने, पाठ्यक्रमों के सुधार, परीक्षा पद्धति में सुधार एवं संस्कृतिमूलक, रोजगारपरक शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। दूसरा विषय राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत युवाओं में प्रेरणास्पद संचार का प्रसार एवं जनजागृति जैसे प्रयास शामिल हैं। तीसरा विषय विकास से जुड़ा है। अभाविप प्रयास करती है कि युवाओं में विकास की धारा प्रवाहित की जा सके, जिससे उनका व्यक्तित्व उभर कर आए जो समाज की संरचना का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा।

एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है युवाओं के रोजगार का, इस देश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए?

रोजगार जैसे विषय की पूर्ति मात्र सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए एक श्रम संस्कृति खड़ी करने की जरूरत होगी, जिससे सरकार और नागरिकों की परस्पर भागीदारी से इस समस्या से लड़ना होगा। तभी लोगों में शारीरिक मानसिक श्रम की संस्कृति विकसित होगी। परिणामतः आत्मगौरव का संचार होगा और लोग समाज में अपेक्षित दर्जा हासिल कर सकेंगे।

सबसे बड़ी जरूरत आज पाठ्यक्रमों को नये सिरे से तैयार करने की है, जिससे परंपरागत विषयों को अधिक रोजगारपरक बनाया जा सके। जैसे कि इतिहास के साथ पुरातत्व विज्ञान, हिन्दी भाषा के साथ जनसंचार; इस तरह से कोर्स तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना है कि सरकार का इस तरफ ध्यान नगण्य है। भारत को आर्थिक सत्ता बनाने के लिए निचले स्तर से सोचना पड़ेगा, जिससे गरीबों, ग्रामीणों, किसानों, पिछड़ों तथा आदिवासियों के हित सुरक्षित रह सकें और तभी गांव पुनः पूर्ण सत्ता बन सकेंगे। ■

CPM recaptured Nandigram: Party Hired Goons, Used Black Money

For the first time in the 30-year Left Front regime in Bengal, the ruling CPM stood in complete isolation over Nandigram, with its partners refusing to take the onus of the red terror. So when CPM state secretariat member Shyamal Chakrabarty announced on Sunday evening that Nandigram was "free from terror", three partners - Forward Bloc, RSP and CPI - distanced themselves from Alimuddin Street. They put the entire blame of the bloodbath on CPM and denounced the arrest of cultural activists who took to the streets on Sunday protesting the recapture of the Nandigram villages.

"CPM is solely responsible for the gory course of events in Nandigram," CPI state secretary Manju Majumdar said following a meeting of the three parties, putting up a front within the Front. The tenor of the resolution sounded similar to what governor Gopalkirshna Gandhi termed as "unlawful and unacceptable" the other day, and drew flak from CPM state secretary Biman Bose.Congress too accused (but couldn't enforce president rule in West-Bengal because they don't want any unwarranted situation at the centre) the Buddhadeb Bhattacharjee regime in West Bengal of abdicating its responsibility to protect people and wondered whether its writ ran in Nandigram.

In Tamluk, party supporters took out a rally to celebrate their "victory" where East Midnapore district secretariat member Asok Guria announced the "recapture" of Nandigram. The last line of resistance by the Trinamul Congress-led Bhumi Uchchhed Pratirodh Committee, spearheading the agitation against the West Bengal government's land acquisition drive, had crumbled. The Centre is sending a "senior officer" to assess the situation. By the time Trinamul chief Mamata Banerjee and CRPF men reached the war zone, CPM's "Operation Nandigram" was over. Policemen stood as mute spectators while CPM cadres stormed villages. But in Kolkata, the cops turned proactive and blocked a procession of artists and intellectuals, and lathicharged the peaceful rally.

The plan to recapture Nandigram was drawn two weeks back in a meeting between two top CPM leaders from East and West Midnapore.

The first attempt to re-enter the villages and oust Bhumi Uchchhed Pratirodh Committee supporters, who had held fort since early 2007, was made on March 14. The operation was conducted mainly by state police and did not bring the desired result. CPM had to go on the backfoot following widespread protests after the March 14 massacre. Since then no CPM leader has been able to set foot in Nandigram.

The war zone was still out of bounds for the media on Sunday but the gory scene of the dead and dying at Tamluk hospital told its story. A 40-year-old woman from Satengabari village, laying on bed no. 14 in Tamluk district hospital, narrated her ordeal: "it was about 8 pm last Tuesday (a day after the final onslaught from Khejuri was launched). My husband was not at home. I was in bed with two teenage daughters when five men barged in.

About 25 others stood guard outside. They pulled me by the hair and one of them raped me. Our two daughters were also pulled out and raped by four people. They hit me with rifle butts." She lay dazed in her house for a day before her nephew brought her to the Nandigram block hospital. Later, she was shifted to Tamluk. "I still don't know what has happened to my two daughters," she said. ■

Madhya Bharat

क्रांति संदेश यात्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1857 की क्रांति के 150 वीं वर्षगांठ पर क्रांति संदेश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रैली निकाली गई एवं स्थानीय आजाद चौक पर अभाविप का सम्मेलन हुआ।

विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली गई क्रांति संदेश यात्रा मुख्य उदेश्य युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव जगाना था। कार्यक्रम की शुरूआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती व सवामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में प्रांतीय मंत्री भारत पारख ने 1857 के डेढ़ सौ वर्ष बीत जाने पर निकाली जाने वाली क्रांति संदेश यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि मंगल पांडे, अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह, आदि शहीदों को नमन किया जाना चाहिए। प्रांता अध्यक्ष क्षितिज पुरोहित ने सन् 1857 से लेकर सन् 1947 तक के संघर्ष के संबंध में उल्लेख करते हुए कहा कि केवल 27 वर्षो का संघर्ष देश के अमर शहीद क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। क्रांति संदेश यात्रा के संबंध ा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने पअने विचार व्यक्त किया। क्रांति संदेश यात्रा नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए सभा स्थल तक पहुंची।

क्षेत्रीय सेवा प्रमुख श्री गोरेलाल बारछे ने श्री फल फोड़कर शुभारंभ किया। यात्रा संयोजक श्री रवि जायसवाल, सह–संयोजक श्री सचिव दवे, नगर उपाध्यक्ष श्री दलसिंह, नगर मंत्री श्री अंकुर पाठक उपस्थित थे। संचालन विभाग संयोजक श्री पुष्पमित्र भार्गव ने किया।

प्रांतीय जनजातिय सम्मेलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय जनजातीय विद्यार्थी सम्मेलन सोमवार को यहां आईटीआई कॉलेज में हुआ। अध्यक्षता पेटलावद विधायक सुश्री निर्मला भूरिया ने की। मुख्य वक्ता अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा थे। सम्मेलन में जनजातिय समस्याओं एवं छात्रावासों में उत्पन्न अव्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य वक्ता श्री शर्मा ने कहा कि इस देश में जब–जब विपत्ति आई है, युवा उन समस्याओं को लेकर लड़ा है। हमारे देश में रामायण को कपोलकल्पीत कथा कहा जाता है एवं आजादको आंतकवादी कहकर क्रांतिकारी का अपमान करने का दुस्साहस किया जाता है।

विधायक सुश्री भूरिया ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् देश के युवाओं में राष्ट्रीयता जगाने का कार्य कर रहा है। अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री कमलेशसिंह ने परिषद की उपलब्धियों पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में समाज द्वारा आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा, टटीया मामा, रघुनाथसिंह मंडलोई आदि क्रांतिकारियों के संबंध में चर्चा की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री कमलेशसिंह, प्रांत संगठन मंत्री श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रांत मंत्री श्री भारत पारख आदि उपस्थित थे। संचालन प्रांत सह मंत्री श्री कालूसिंह मंडलोई ने किया आ[illegible] नगर अध्यक्ष श्री दिनेश चौहान ने माना।

Himachal Pradesh

Kranti sandesh yatra ends in Hamirpur

The nine day old Kranti Sandesh yatra of the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad, ended with the pledge to work for the national unity and remember all those who had laid down their lives for the nation's freedom struggle. The ABVP considers the 1857 revolution as the start of India's freedom struggle from the clutches of Britishers.

During this yatra that started from four separate places, the ABVP activists visited almost all parts of the state in various vehicles and gave people the message behind their yatra. They told the people that the history of India's freedom struggle date back to year 1857 and not later on as mentioned in various history books. They reminded people that the Indian history was distorted and the main aim of the yatra was to tell the people how the 1857 revolution started and how it ended.

While addressing the students at a huge rally here today, Mahant Surya Nath, the President of Himachal VHP said that the 1857 revolution was

one of the biggest and successful most revolution of world in which about three and half lakh people had sacrificed their lives for the nation. It was due to this revolution that the road was made for the liberation of India in year 1947.

He gave a clarion call to the youth of India to tell their counterparts the old and real history of India and its freedom struggle and create an awareness of revolution amongst them. He said that building of national character was the need of the hour and youth should play a major role in this field.

Sanjay Kumar, the Param Veer Chakra winner of Kargil war said that youth should channelise their energy for good cause and should desist from such forces who try to use them for their own selfish ends. He narrated the story of Kargil war that gave him India's highest gallantry award.

Karnatak

Deshabhakti Rathyatra given warm welcome

In Belgaum, when ABVP's Deshbhakti Rathyatra arrived, hundreds of students of various colleges welcomed the Yatra at Rani Chennamma Circle.

Freedom fighters Vithal Yalagi and Vinay Jadar garlanded the statue. The Yatra further proceeded to the samadhi of Nargundkar Babasaheb near Jyoti College and paid tributes in the memory of the leader.

Addressing students at Jyoti College, Alakatai Inamdar of Rashtra Sevika Samiti, expressed anguish at the present generation's lack of regards to the freedom fighters who fought the foreign yoke and brought them freedom. Jyoti College principal Jadhav exhorted youth to make Bhagat Singh their rolemodel.

The Yatra culminated at Gomatesh Vidyapeeth. Vidyapeeth's chief Sanjay Patil welcomed it. Speaking on the occasion, ABVP state Organising Secretary Ravi Kumar explained the need and importance of the Yatra.

ABVP has organised the Yatra to celebrate the 150 years of the freedom struggle and the centenary year celebrations of the birth anniversary of Bhagat Singh.

Delhi

प्रान्तीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली प्रांत का 43वां प्रान्तीय अधिवेशन 27–28 अक्टूबर को पंजाबी बाग स्थित सनातन धर्म सरस्वती बाल मन्दिर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में दिल्ली में स्थित विश्वविद्यालयों से 135 संख्या रही। अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक जितेन्दर बजाज जी, मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट जी ने दीप प्रज्जवल कर किया। राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट जी ने छात्रों को सम्बोधित करते हुय कहा कि विद्यार्थी परिषद् किस तरह से छात्रों की साइकिल स्टैंड की समस्या से लेकर, राष्ट्रीय समस्याओं तक के लिये संघर्ष करती है।

अधिवेशन में भाषण सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री मा. सुनील बंसल जी ने आजादी के 60 वर्ष पूरे होने पर देश की उपलब्धियां व चुनौतियों के बारे में विस्तृत भाषण दिया। अधिवेशन में दो प्रस्ताव सदन में रखे गये। पहला प्रस्ताव – प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति, विषय पर सुरेन्द्र सिंह ने रखा। दूसरा प्रस्ताव – प्रदेश की शैक्षणिक स्थिति पर रोहित चहल ने रखा। दोनों प्रस्ताव सदन में कुछ संशोधन के उपरांत पारित किया गया।

प्रदेश मंत्री निहारिका शर्मा ने दिल्ली की पूरे वर्ष भर में हुई परिषद गतिविधियों का वृत्त रखा। समारोप सत्र में प्रदेश संगठन मंत्री ने छात्रों से अपील की वे अपने–अपने क्षेत्र में जाकर विद्यार्थी परिषद् के कार्य को आगे बढ़ाये। अधिवेशन में पुनः प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश मंत्री के लिये राजकुमार शर्मा जी व निहारिका शर्मा का चुनाव हुआ। इसके उपरांत अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमें –

उपाध्यक्ष – वीरेन्द्र सिंह , सतबीर जैन , राजकुमार , रामकुमार वर्मा। सहमंत्री – देवेन्द्र भारद्वाज, रोहित चहल, सत्यदेव चौधरी, ईशा टोकस, विकास दहिया, आनंद भाटी।

Kerala

State conference held

The 27th State Conference of ABVP was held at Palakkad on 2-4 November. The conference was inaugurated by all-India vice-president Shri Murali Manohar.

"The ABVP unlike other student organisations aimed to mould the youth into responsible citizens and bring about social change" he said. He also said that political change alone would not bring about a social change. There were a large number of social problems faced by the people and the students within the campus. The mission of the ABVP was 'man making' while the goal of other student organisations was to bring some political party to power.

In the early eighties, the students and people from Assam, Meghalaya and the North East felt that they were not part of India and were left out. But it was the organisations like the ABVP who brought the students from the North East to New Delhi and other places every year who by seeing our culture began to identify themselves as part of our great country.

Vidya Bharathi all-India president P.K. Madhavan said organisations like the ABVP taught the students not only their rights but also their duties.ABVP state president S Manu delivered the introductory speech. Reception committee general secretary R. Manikantan welcomed the gathering.

Three resolutions were passed in the conference.State Organising Secretary Shri T Sudeesh spoke at the validectory session of the conference.

A rally and public programme was also conducted as part of the conference which was inaugurated by All India Secretary Shri P Sandeep.

The conference elected Adv.S Manu as State President and Shri Sudheer as Secretary.

Swatanthrya Samara Sandesh yatra Conducted.

Swatanthrya Samara Sandesh yatra was conducted by ABVP Kerala Unit on 22-29 November to celebrate the 150 years of the first freedom struggle and the birth centenary of Bhagat Singh.

The yathra visited around 50 colleges and 10 towns of the districts of Thiruvananthapuram to Palakkad. ABVP all India Secretary Shri Vishnu Dutt Sharma inaugurated the yathra at VTM NSS college, Thiruvananthapuram.

Andhra Pradesh

Two day training classes for university students organised

It is unfortunate that the students of a country which has great traditions in education are now looking at foreign shores for higher education, said Swadeshi Jagaran Manch State organisation secretary Appala Prasad.

Addressing the valedictory of the two-day training classes for university students organised by the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) at Nizamabad, he called upon the university students to fight for a National Educational Teaching System (NETS).

The European and Americans had begun research into the secrets of the Vedas.He lashed out at educational policies and programmes of the Congress-led UPA government and pointed out lapses in the functioning of educational institutions.

Osmania University professor Narsingh Rao, ABVP national secretary Guntha Laxman, ABVP Andhra-Tamil Nadu state in charge Manthri Srinivas,participated.The two-day programme was attended by 200 students from different universities across the State. ■

जम्मू प्रांत का अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट

लेह–लद्दाख में आयोजित सम्मेलन में बोलते हुये मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर और उपस्थित छात्र

1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ पर बरेली में शहीद स्तम्भ पर 1857 दीप प्रज्जवलित करते परिषद् कार्यकर्ता

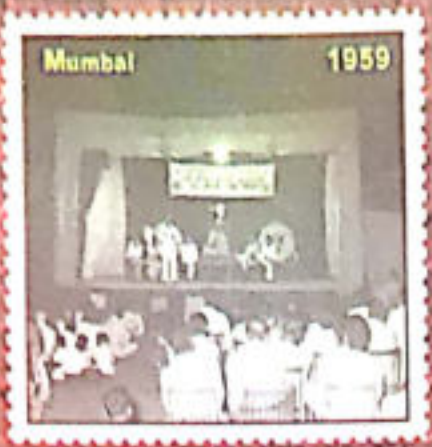

एक छात्र संगठन की
विजय यात्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद